सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 174, नई दिल्ली, सोमवार 01 सितम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है "भरोसा"

03 जहांगीर पुरी में सड़को पर पशुओं का जमावड़ा, लोग हो रहे है परेशानः भास्कर

06 सेल्फ लर्निंग फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन है

08 राहुल गांधी आदेश दें तो झारखंड में भाजपा के सभी कार्यालय तोड़ देंगे : डा० इरफान अंसारी

फिट इंडिया 800 किलोमीटर साइकिल यात्रा संपन्न, खेल दिवस पर दिखा उत्साह

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का समापन दिल्ली में हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलों को जीवन जीने की कला बताया। प्रयागराज से शुरू होकर यह यात्रा कई शहरों से गुजरी और इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस बार फिटनेस और खेलों का रंग कुछ अलग ही देखने को मिला। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल महोत्सव के तहत आयोजित 800 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा ने देशभर में फिट इंडिया का संदेश फैलाते हुए रविवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समापन किया।

यह यात्रा साइकलिस्ट योगेंद्र सिंह, मदन लाल, डा विक्रम सिंह ने तीन सपोर्ट स्टाफ के साथ साइकिल चलाकर तय की। समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डा. मनसुख मंडाविया विशेष रूप से मौजूद रहे।

केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। फिट इंडिया मूवमेंट स्वस्थ और सक्रिय भारत की दिशा में बड़ा कदम है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को मजबूती देता है।

यह ऐतिहासिक यात्रा 24 अगस्त को प्रयागराज से शुरू हुई थी। रास्ते में फतेहपुर, कानपुर, ओरई, झांसी और ग्वालियर होते हुए दिल्ली पहुंची। प्रयागराज से शुरुआत में 1000 से अधिक साइक्लिंग प्रेमियों ने भाग लिया।

फतेहपुर और कानपुर में जनप्रतिनिधियों व खिलाड़ियों ने दल का स्वागत किया, वहीं झांसी में मेजर ध्यानचंद के परिवार से भी मुलाकात हुई। ग्वालियर में सांसदों और एनसीसी कैडेट्स की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया।

दिल्ली पहुंचने पर इस यात्रा को लोकप्रिय फिटनेस कार्यक्रम संडे आन साइकिल से जोड़ा गया, जिसे भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित किया गया।

प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लेकर फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। यह अभियान पेफी, स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया और ब्रह्माकुमारीज स्पोर्ट्स विंग के सहयोग से आयोजित हुआ। पेफी के राष्ट्रीय सचिव डां. पीयूष जैन ने कहा कि इस यात्रा ने फिटनेस को एक जन आंदोलन का रूप दिया है।

क्या हम भारतीय संसद में नेताओं को जनहित कार्यों के प्रति नियम अधिनियम बनाने के लिए भेजते हैं या गाली गलौज करने, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

- *लोकतंत्र क्या है और हम इसके लिए क्षेत्र से प्रतिनिधि को अपने मतों का प्रयोग कर क्यों भेजते है क्या कभी सोचा है किसी ने।*
- *जनता के द्वारा मतों के द्वारा ही क्यों सरकार बनाई जाती हैं ?*
- *क्या आज की राजनीति सच में जनता के हित के लिए है ?*

नई दिल्ली। हकीकत तो यह है कि आज की राजनीति सत्ता पद और स्वार्थ का खेल बनकर रह गई है। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहां जनता द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजे गए नेता समाधान निकालने के बजाय गाली-गलौज और हंगामे पर उतर आते हैं।

जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये खर्च कर संसद चलाई जाती हैं, लेकिन नतीजा शून्य। जनता का पैसा हो रहा हैं बर्बाद और उसके बदले फल शून्य और साथ ही भर जाती हैं नेताओं की जेब। बिना मेहनत कमाई खाने की भूख ने राजनीति को खोखला कर दिया है।

अब सवाल यह उठता है की जनता की समस्याएँ कौन उठाएगा जब चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी जेब भरने पर उतारू हो जाएगा और जनता की परेशानियों को संसद में उजागर कर उसके लिए हल की मांग ही नहीं करेगा ?

सड़कों की हालत खस्ताहाल, गाँव- शहर में लोग परेशान, स्वास्थ्य और शिक्षा बदहाल, लेकिन संसद में बैठे नेता इन मुद्दों पर चुप्पी साधे गाली गलौज कर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने में लगे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए और जाति-धर्म की राजनीति चाहिए।

हमारी गलतियों का परिणाम और विडंबना है कि एक अनपढ़ नेता के समक्ष बेबस वर्षों की कठिन परीक्षा पास करके बना अधिकारी हाथ जोड़कर खड़ा होता है।

यह कैसा लोकतंत्र है ? क्या यही व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने सोची थी जहाँ काबिलियत की नहीं, सिर्फ सत्ता की हैसियत की कद्र हो।

नेता चुनावों में वादों की झड़ी लगाते हैं और कुर्सी पर बैठते ही जनता को भूल जाते हैं। संसद को अखाड़ा बनाकर उसकी गरिमा का बार-बार अपमान कर रहे है।

अभी भी समय है जनता जागरूक बने और जो नेता सिर्फ अपने लालच के लिए संसद नहीं चलने देते, जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, नफ़रत और हंगामा फैलाते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू करे।

जब तक राजनीति को सेवा और समर्पण का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक लोकतंत्र खोखला ही रहेगा। संसद मंदिर तभी कहलाएगी, जब संसद में जनता की आवाज़ गूंजेगी ना की नेताओं की गाली-गलौज।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत के सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए गूगल फार्म पर क्लिक करें और भरकर जमा करे, पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट (पंजीकृत अंडर सेक्शन 60), नीति आयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एमएसएमई में पंजीकृत
https://forms.gle/VEThcFgMcknGFc1u9

TEMPLE OF LIBERALIZATION AND SOCIAL WELFARE ALLIED TRUST REGT.

MEMBERSHIP FORM FOR TOLWA TRUST

transportvisheshcontent@gmail.com Switch account

The name, email, and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form

* Indicates required question

How you got aware about TOLWA trust *

- Social Media
- News Paper
- Personal connection
- Youtube
- Social Function/ RTO/friends/family

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

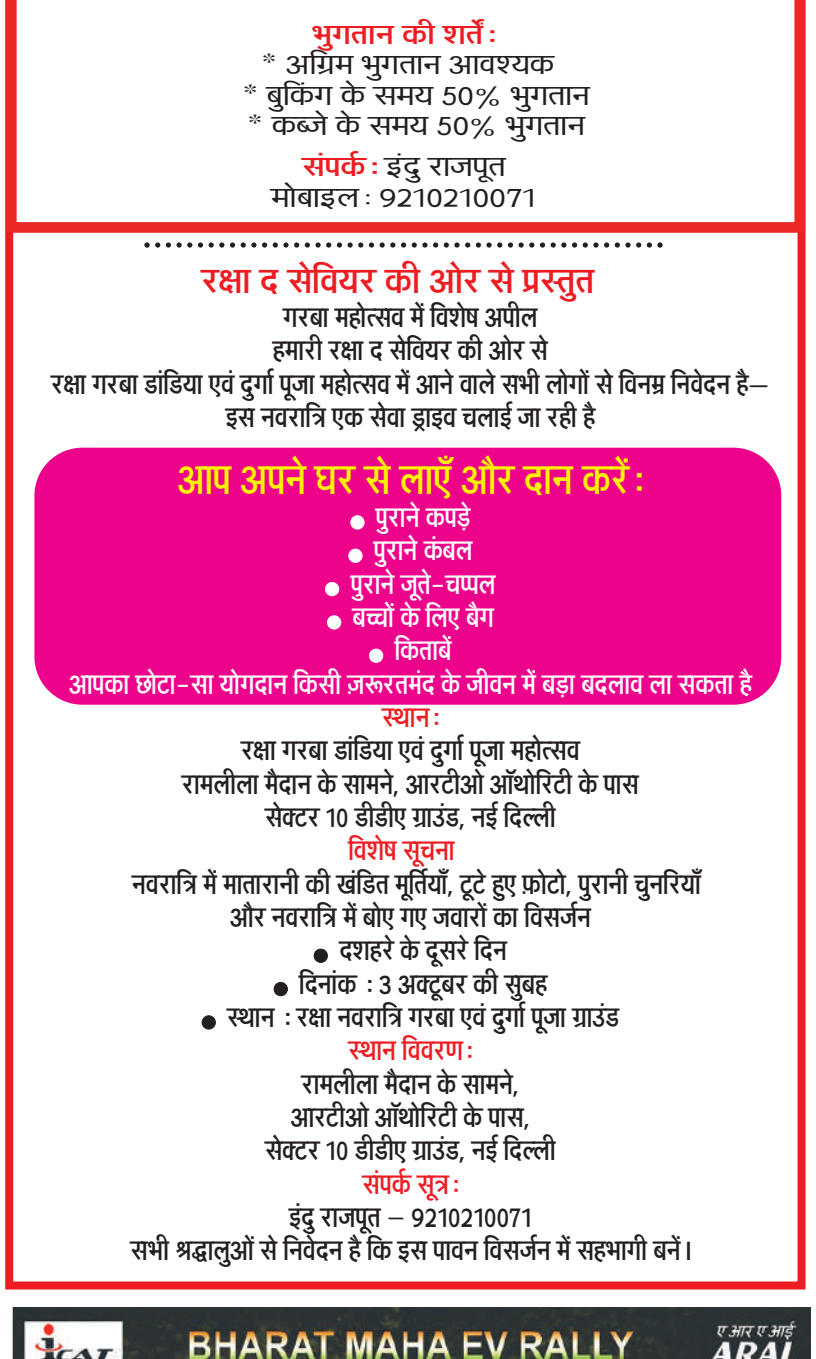

स्टॉल प्रस्ताव :
सिंगल साइड ओपन स्टोल : 2000
कॉर्नर साइड स्टोल : 3500
तीन साइड ओपन स्टोल : 4500
सिर्फ एक टेबल : 1000
सिर्फ दो टेबल : 1250

कार्यक्रम विवरण :
रक्षा गरबा–डांडिया और दुर्गा पूजा महोत्सव
स्थान : डीडीए ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड के सामने, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बगल में, PNB बैंक के पीछे, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075

तारीखें : 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025
* दुकान का आकार : 10 फीट x 10 फीट
* शामिल सुविधाएँ :
* 2 कुर्सियाँ * 2 टेबल
*लाइट व चार्जिंग प्वाइंट

भुगतान की शर्तें :
* अग्रिम भुगतान आवश्यक
* बुकिंग के समय 50% भुगतान
* कब्जे के समय 50% भुगतान

संपर्क : इंदु राजपूत
मोबाइल : 9210210071

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है–
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

उज्जैन का चिंतामन गणेश मंदिर: भक्तों की चिंताएँ हरने वाले इस मंदिर में भगवान गणेश मूर्ति रूप में स्वयं हुए थे प्रकट

उज्जैन में स्थित चिंतामन गणेश मंदिर श्रद्धा और रहस्य का अद्वितीय केंद्र माना जाता है। यह मंदिर भगवान गणेश के उन चार प्रसिद्ध स्वयंभू गणेश मंदिरों में से एक है, जहां भगवान गणेश मूर्ति रूप में स्वयं प्रकट हुए थे।

चिंतामन' का अर्थ है चिंताओं को हरने वाला। इसलिए, मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके जीवन की सारी परेशानियाँ और चिंताएँ दूर हो जाती हैं। यहाँ के गणेशजी चिंता दूर करने वाले और विघ्नहर्ता माने जाते हैं। यह मंदिर उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है।

इसे उज्जैन के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है।

चिंतामन गणेश जी की खासियत

पौराणिक मान्यता है कि मूल मंदिर रामायण काल का है और इसकी स्थापना सीता ने की थी । स्वयं सीता माता ने रामजी के साथ वनवास काल में यहाँ पूजा की थी। मंदिर में भगवान गणेश के तीन रूप विराजमान हैं - चिंतामण जो श्रीराम द्वारा स्थापित हैं।

दूसरा इच्छामण, जो लक्ष्मण द्वारा स्थापित है और तीसरा सिद्धिविनायक, जो माता सीता द्वारा स्थापित है। यह त्रिस्वरूप स्थापना इसे अन्य गणेश मंदिरों से विशिष्ट बनाती है। यहाँ

गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं। मंदिर में हनुमान जी की पाँच मूर्तियाँ भी हैं, जो साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। गर्भगृह में गणेश जी की मूर्ति आधी भूमि में धंसी हुई है, जो अत्यंत दुर्लभ है।

यहाँ विराजित गणेशजी की मूर्ति स्वयंभू (स्वतः प्रकट हुई) मानी जाती है, जिसे मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया। भक्त मानते हैं कि भगवान गणेश स्वयं यहाँ विराजमान होकर अपने भक्तों की चिंताएँ हरते हैं। एक मान्यता यह भी है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसे श्रीयंत्र की संरचना के अनुसार बनवाया था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की पूजा और तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वयं को मूर्ति स्वरूप में प्रकट किया और यहीं विराजमान हो गए। वैसे, इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर परमार वंश के काल (लगभग 11वीं सदी) का है।

गणेश चतुर्थी में इस मंदिर में काफी भीड़ होती है। विवाह, संतान, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए यहाँ विशेष पूजन किया जाता है। हजारों भक्त मानते हैं कि यहाँ गणेशजी की आराधना करने से चिंता, दुख और विघ्न स्वतः दूर हो जाते हैं।

चैत्र माह के बुधवार को विशेष पूजा होती है। श्रद्धालु मन्नत का धागा बांधते हैं और उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। यह परंपरा केवल इसी मंदिर में प्रचलित है। यहाँ किसान अपनी फसल कटने के बाद सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं, जिससे कृषि कार्यों में बाधा दूर होती है।

सूर्य की 12 कलाएँ (द्वादश कला)

सूर्य की 12 कलाएँ (द्वादश कला) भी वैदिक और पुराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं।

ये कलाएँ सूर्य के बारह रूप मानी जाती हैं, जो साल के 12 मास और 12 राशियों से भी जुड़ी हैं।

हर कला एक विशिष्ट ऊर्जा, गुण और प्रभाव रखती है।

सूर्य की 12 कलाएँ

(संस्कृत नाम + संक्षिप्त अर्थ)

1. Tapini (तापिनी) – ऊष्मा और जीवन देने वाली शक्ति
2. Tapini-ā (तापिनीआ) – तप और बल को बनाए रखने वाली
3. Dhūmrā (धूम्रा) – धुँधलापन, मेघ और वर्षा से जुड़ी
4. Marīci (मरीचि) – किरणों का स्रोत
5. Sphaṭikā (स्फटिका) – निर्मलता और पारदर्शिता
6. Sudarśanā (सुदर्शन) – शुभ दृष्टि और स्पष्टता
7. Kha (ख) – आकाशीय विस्तार की शक्ति
8. Viśvakarmā (विश्वकर्मा) – सृजन और निर्माण की ऊर्जा
9. Viśva-rūpā (विश्व-रूपा) – समस्त रूपों में व्यापी
10. Sāmā (सामा) – संतुलन और समरसता

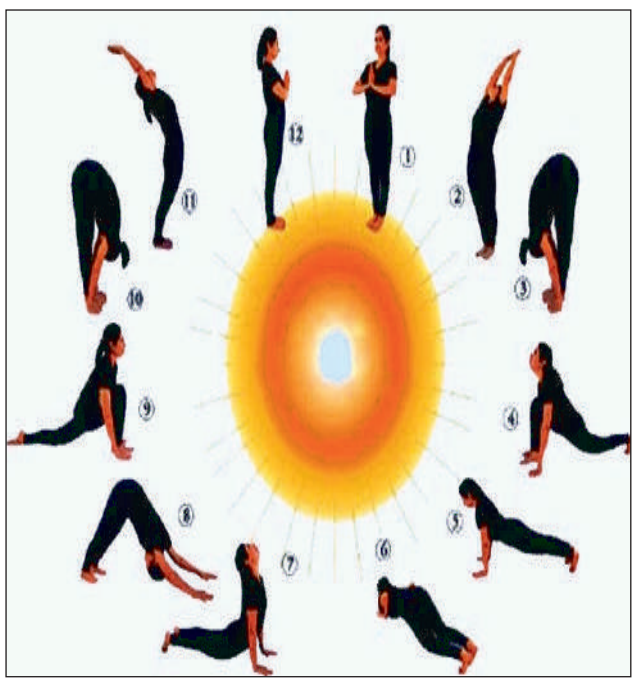

11. Sarvātmā (सर्वात्मा) – सबके आत्मा में स्थित
12. Vyāpinī (व्यापिनी) – सर्वत्र व्याप्त रहने वाली

महत्व

* ये 12 कलाएँ सूर्य के द्वादश आदित्य (मासिक रूप) से जुड़ी हैं — जैसे मित्र, रवि, सविता, भानु, पूषा, अर्क, आदि।

* वैदिक ज्योतिष में इन्हें 12 राशियों और सूर्य के वार्षिक चक्र से जोड़ा गया है।

* योग में ये 12 कलाएँ प्राण-ऊर्जा के 12 मुख्य प्रवाह मानी जाती हैं, जो साल भर अलग-अलग समय पर प्रबल होती हैं।

थायरॉइड के उपाय एवं उपचार

"उपाय...1" :-
खाली पेट
1 चम्मच अलसी का चूर्ण दिन में 3 बार।
1 चम्मच धनिया पाउडर 1 बार।
1 चम्मच बड़िसोप 1 बार।
आप इसे बिना चूर्ण के खा सकते है या सुबह गर्म पानी के साथ ले सकते है।
इसे 3 महीने तक रोज़ाना
खाली पेट ले।

"उपाय...2" :-
सुबह नहाते समय, अपने मुँह में गर्म पानी भरें और नहाने के बाद तक पानी को ऐसे ही रखें। इससे थायरॉइड ग्रंथि सक्रिय होती है और सुचारू रूप से काम करती है।

"उपाय...3" :-
अनुलोम विलोम प्राणायाम 7 मिनट।
उज्जायी प्राणायाम 10 मिनट।
कपालभाति 10 मिनट।
यह प्राणायाम रोज़ सुबह और शाम करें।

"उपाय...4" :-
अगर आपका वज़न बढ़ गया है, 20 मिलीलीटर कद्दू का रस पिएँ।
एक गिलास गर्म पानी में 20 मिलीलीटर एलोवेरा का रस और 10 बूँद तुलसी का रस मिलाएँ।

"उपाय...5" :-
रोज़ाना तांबे के बर्तन का पानी पिएँ।

"उपाय...6" :-
एक कलम के आकार की 4 नारियल की जड़ें लें और उनका काढ़ा बनाकर 21 दिनों तक रोज़ शाम को पिएँ।

"उपाय...7" :-
रात को दाँत ब्रश करके सो जाएँ। सुबह उठते ही अपनी लार से अपनी थायरॉइड ग्रंथि को स्पर्श करें और उसे 10 से 12 बार हल्के हाथों से रगड़ें।

"उपाय...8" :-
एक गर्म सूती कपड़े की पट्टी बनाएँ जो थायरॉइड ग्रंथि को स्पर्श करे और रात में 30 मिनट तक रखें।

"उपाय...9" :-
रोज़ाना सोते समय सोने का कोई आभूषण इस तरह रखें कि वह रात भर थायरॉइड ग्रंथि को स्पर्श करे।

"उपाय...10" :-
अपने आहार से सफेद नमक का प्रयोग बंद कर दें और उसकी जगह
सैंधव नमक और काला नमक इस्तेमाल करें।

"उपाय...11" :-
एक मुट्ठी चंदन का चूर्ण, एक मुट्ठी नीम के पत्ते लें और चूर्ण को उबालकर 21 दिनों तक रोज़ रात को सोते समय अपनी थायरॉइड ग्रंथि के पास गर्म रखें।

"उपाय...12" :-
चूँकि अत्यधिक तनाव आपकी बीमारी का मूल कारण है, इसलिए तनावमुक्त जीवन जीने, पर्याप्त नींद लेने और सुखी जीवन जीने का प्रयास करें। योग प्राणायाम ध्यान आहार से आप अपनी बीमारी को 100% ठीक कर सकते हैं।

प्रेम पच्चीसा (भाग 17)

राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर,छत्तीसगढ़

जेल से रिहा बंदिनी अनीता को उसकी सगी लड़की अपने पास रखने से मन करती है तो सुरक्षा कर्मी स्थानीय थानेदार के सहयोग से अनीता के पति के घर छोड़ आते है। कुछ दिन तक अनीता अपने घर मे न रहती लेकिन पति ताने और शारीरिक और मानसिक कष्ट से अनीता घर छोड़कर बिना किसी को बताए अज्ञात जगह भाग जाती है।

अनीता घर से भागी तो उसके पैरों में जैसे नई जान आ गई थी। वर्षों ससुराल की ज़िल्लत भरी ज़िंदगी फिर जेल की सजा ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था लेकिन मन की पीड़ा ने उसे और मज़बूत बना दिया। वह रात के अंधेरे में शहर की गलियों से गुजरती हुई, बिना किसी मंजिल के चलती रही। पीछे छूट गया था वह घर, जहां कभी प्यार की उम्मीद थी, लेकिन अब सिर्फ ताने और मारपीट। उसकी बेटी, जो उसकी सगी थी, ने भी मुंह फेर लिया था। ₹मां कैद में थी, अब समाज क्या कहेगा?₹ यही बहाना था। पति का लांछन था कि अनीता का चरित्र ठीक नहीं था।

अनीता सोचती, क्या बाज़ार की यह संस्कृति इतनी क्रूर है कि रिश्ते भी खरीद-फरोख्त की चीज़ बन गए हैं? जहां व्यक्तिगत स्वार्थ परिवार की नींव हिला देता है। सुबह होने से पहले वह एक छोटे से बस स्टैंड पर पहुंची। जेब में कुछ पैसे थे, जो जेल से रिहा होने पर मिले थे। वह बस में सवार होकर दूर के एक गांव की ओर निकल पड़ी, जहां उसकी एक पुरानी सहेली रहती थी – राधा। राधा भी जीवन की ठोकरें खा चुकी थी लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अनीता को याद आया, जेल में राधा ही थी जो कहती थी, ₹जीवन कैदखाने से बाहर भी कैद जैसा है लेकिन खुद को आजाद करने की चाबी तेरे पास है।₹ गांव पहुंचकर अनीता राधा के घर गई। राधा ने उसे देखते ही गले लगा लिया। ₹अनीता दीदी, तुम आ गईं? मैंने सुना था तुम रिहा हो गई हो। अनीता ने सारी कहानी सुना दी बेटी का इनकार, पति की क्रूरता, और परिवार का टूटना। राधा ने कहा, ₹यह दौर ही ऐसा है, दीदी। बाज़ार ने सबको सिखा दिया कि प्यार नहीं, पैसा और स्टेटस महत्वपूर्ण है।

पति-पत्नी का रिश्ता अब सौदा बन गया है, मां-बेटी और बाप – बेटे का बंधन भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ रहा है। लेकिन हम जैसे लोग ही बदलाव ला सकते हैं।₹ राधा एक छोटा सा महिला स्व सहायता केंद्र चलाती थी, जहां पीड़ित महिलाएं आतीं। अनीता को वहां काम मिल गया – सिलाई सिखाना, बच्चों को पढ़ाना। धीरे-धीरे अनीता ने ख़ुद को संभाला। लेकिन एक दिन उसकी बेटी का फोन आया। ₹मां, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी समाज से। पापा ने भी दबाव डाला था । अब मैं अकेली हूं, मेरे पति ने भी मुझे भी घर से निकाल दिया क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए आवाज उठाई।₹

अनीता का दिल पिघल गया, लेकिन उसने कहा, ₹बेटी, रिश्ते टूटते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, लेकिन मजबूत नींव पर। आ जा बेटा - यहां, हम साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे।₹ कुछ महीनों बाद, अनीता, राधा और उसकी बेटी ने मिलकर एक छोटा सा सामुदायिक स्व सहायता केंद्र खोला, जहां टूटे परिवारों को जोड़ने का काम होता। वहां सिखाया जाता कि बाज़ार की चकाचौंध में खोए रिश्तों को कैसे बचाया जाए। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, प्यार और समझदारी से। अनीता अब कैद की बंदिनी नहीं थी, बल्कि आजादी की मिसाल बन गई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती – जीवन की जंग जारी थी, और हर दिन नई चुनौतियां लाती। क्या अनीता का पति कभी लौटेगा? या समाज बदलेगा? समय बताएगा..

जड़, चैतन्य, ब्रह्म

जड़ को जानना विज्ञान है विज्ञान वस्तु, पदार्थ, नियम, ऊर्जा, समय, स्थान और परिवर्तनशील जगत का अध्ययन करता है। यह सब जड़-तत्व की अभिव्यक्ति है।
चैतन्य को जानना आध्यात्म है। आध्यात्म ₹आत्म₹ से जुड़ा है। आत्मा या चेतना का अध्ययन केवल तर्क या प्रयोगशाला से नहीं, बल्कि अनुभव, ध्यान, तप, अंतर्दृष्टि/दिव्यदृष्टि से होता है।
ब्रह्म को जानना विज्ञान व आध्यात्म दोनों है। ब्रह्म वह मूल है जिसमें जड़ और चैतन्य दोनों एक साथ समाहित हैं।
क्योंकि कद व चैतन्य दोनों में ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानना मतलब दोनों को एक ही सत्य में देखना है।
"जड़ का बोध विज्ञान है,
चैतन्य का बोध आध्यात्म है,
और ब्रह्म का बोध विज्ञान और आध्यात्म दोनों की संपूर्णता है।"

जब हमारे प्रयासों की सराहना नहीं होती, तो ?

प्रशंसा सबको पसंद है!!! प्रशंसा प्रेरणा देती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स हमें पसंद है, जितनी ज़्यादा हमारी सराहना होती है, उतना ही ज़्यादा हम मूल्यवान महसूस करते हैं, और उतना ही ज़्यादा हम योगदान देना चाहते हैं, उतना ही ज्यादा हम, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं।

कभी-कभी, हम यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे आस-पास के लोगों का जीवन सुचारू रूप से चले, सब खुश रहें। हम, दुसरों की हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, और दूसरों को आराम पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालाँकि, जब हमारे प्रयासों को लाइक्स रुपी मान्यता नहीं मिलती, तो हम अप्रशंसित और निराश महसूस कर सकते हैं। कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है।

अगर दूसरे हमारी मेहनत को न पहचान पाएँ, तो निराश क्यों हों ? हालाँकि जब हमारे प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो यह हमारे लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन हमें यह याद रखना ज़रूरी है कि खुद जरा से भी कमतर नहीं है, हम प्रयासरत हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। आख़िरकार, लोग जानते हैं कि हम अपने आस-पास के लोगों के जीवन को कितना बेहतर बना रहे हैं।

आजकल हम सोशल मीडिया द्वारा तय करने लगे हैं कि कौन हमें पसंद करता है और कौन नहीं!!! लेकिन क्या यह सही है ? मोदीजी को सोशल मीडिया में चार से पांच करोड़ लोग फोलो करते हैं, लेकिन उनके नाम से भाजपा को तीस से पैंतीस करोड़ वोट मिलते है, जो उनके चाहने वाले है। तो क्या मोदीजी कि लोकप्रियता सोशल मीडिया तय कर सकता है ? नहीं ऐसे बहुत से लोग है जो हमें चाहते है लेकिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया करते !!! यह बात समझनी पड़ेगी कि लाइक्स पैमाना नहीं है, हमारा विश्वास, हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारे कार्य ओर हमारी भावनाएं तय करती है कि लोग हमें कितना चाहते है।

खुश रहो, प्यार से रहो, मजबूत बनो, चिंता मत करो.....खुद से प्यार करो, जीवन के हर पल का आनंद लो...जीवन सुंदर है, खूब खुलकर जीओ।

सदा_मस्त_रहें, स्वस्थ_रहें।

क्यों करना चाहिए रुद्राभिषेक

रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने और मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता मिलती है, साथ ही दरिद्रता, बाधाएं, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. शिव पुराण के अनुसार यह एक अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र अनुष्ठान है, जिसे करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में ग्रहों की नकारात्मकता दूर होती है.

जन्म से मृत्यु तक कुंडली के 12 भाव:-

1. मनुष्य के लिए संसार में सबसे पहली घटना उसका इस पृथ्वी पर जन्म है इसीलिए प्रथम भाव जन्म भाव कहलाता है जन्म लेने पर जो वस्तुएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं उन सब वस्तुओं का विचार अथवा संबंध प्रथम भाव से होता है जैसे- रंग-रूप, कद, जाति, जन्म स्थान तथा जन्म समय की बातें।
२. ईश्वर का विधान है कि मनुष्य जन्म पाकर मोक्ष तक पहुंचे अर्थात प्रथम भाव से द्वादश भाव तक पहुंचे जीवन से मरण यात्रा तक जिन वस्तुओं आदि की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है वह द्वितीय भाव से एकादश भाव तक के स्थानों से दर्शाई गई है।
3. मनुष्य को शरीर तो प्राप्त हो गया किंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तथा ऊर्जा के लिए दूध, रोटी आदि खाद्य पदार्थो की आवश्यकता होती है अन्यथा शरीर नहीं चलने वाला इसीलिए खाद्य पदार्थ, धन, कुटुंब आदि का संबंध द्वितीय स्थान से है।
4. धन अथवा अन्य आवश्यकता की वस्तुएं बिना श्रम के प्राप्त नहीं हो सकतीं और बिना परिश्रम के धन ठिक नहीं सकता धन, वस्तुएं आदि रखने के लिए बल आदि की आवश्यकता होती है इसीलिए तृतीय स्थान का संबंध, बल, परिश्रम व बाहु से होता है।
5. शरीर, परिश्रम, धन आदि तभी सार्थक होंगे जब काम करने की भावना होगी, रुचि होगी अन्यथा सब व्यर्थ है अत: कामनाओं, भावनाओं का स्थान चतुर्थ रखा गया है चतुर्थ स्थान मन का विकास स्थान है।
6. मनुष्य के पास शरीर, धन, परिश्रम, शक्ति, इच्छा सभी हों, किंतु कार्य करने की तकनीकी जानकारी का अभाव हो अर्थात विचार शक्ति का अभाव हो अथवा कर्म विधि का ज्ञान न हो तो जीवनचर्या आगे चलना मुश्किल है पंचम भाव को विचार शक्ति के मन के अन्तर जगह दिया जाना विकास क्रम के अनुसार ही है।
7. यदि मनुष्य अड़चनों, विरोधी शक्तियों, मुश्किलों आदि से लड़ न पाए तो जीवन निरन्तरता नहीं है अत: षष्ठ भाव शत्रु, विरोध, कठिनाइयों आदि के लिए मान्य है।
8. मनुष्य में यदि दूसरों से मिलकर चलने की शक्ति न हो और वीर्य शक्ति न हो तो वह जीवन में असफल समझा जाएगा अत: मिलकर चलने की आदत व सफल वैवाहिक जीवन आवश्यक है और उसके लिए भागीदार, जीवनसाथी की आवश्यकता होती ही है अत: जीवनसाथी, भागीदार आदि का विचार सप्तम भाव से किया जाता है।
9. यदि मनुष्य अपने साथ आयु लेकर न आए तो उसका रंग, रूप, स्वास्थ्य, गुण, व्यापार आदि कोशिशें सब बेकार अर्थात व्यर्थ हो जाएंगी अत: अष्टम भाव को आयु भाव माना गया है आयु का विचार अष्टम से करना चाहिए।
10. नवम स्थान को धर्म व भाग्य स्थान माना है धर्म-कर्म अच्छे होने पर मनुष्य के भाग्य में उन्नति होती है और इसीलिए धर्म और भाग्य का स्थान नवम माना गया है।
11. दसवें स्थान अथवा भाव को कर्म का स्थान दिया गया है अत: जैसा कर्म हमने अपने पूर्व में किया होगा उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा एकादश स्थान प्राप्ति स्थान है हमने जैसे धर्म-कर्म किए होंगे उसी के अनुसार हमें प्राप्ति होगी अर्थात अर्थ लाभ होगा, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ है आज हम इस अर्थ प्रधान युग में।
12. द्वादश भाव को मोक्ष स्थान माना गया है अत: संसार में आने और जन्म लेने के उद्देश्य को हमारी जन्मकुण्डली क्रम से इसी तथ्य को व्यक्त करती है।

जन्मकुण्डली का फल कथन:-

1. जिस भाव में जो राशि होती है उसी राशि के स्वामी ग्रह को उस भाव का भावेश कहते हैं तृतीय, षष्ठ, एकादश भावों के पापी ग्रहों का रहना शुभ माना जाता है।
२. षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव के स्वामी जिन भावों में रहते हैं उसका वह अनिष्ट करते हैं यदि वह स्वग्रही अथवा उच्च न हो तो।
3. अपने स्वामी ग्रह से देखा जाने वाला भाव बलवान व शुभ होता है अष्टम व द्वादश भाव में सभी ग्रह अनिष्ट फलप्रद होते हैं किंतु शुक्र द्वादश स्थान में बहुत प्रसन्न रहता है क्योंकि शुक्र एक भोगात्मक ग्रह है तथा द्वादश स्थान भोग स्थान है छठे भाव अथवा स्थान में भी शुक्र सम्पन्न रहता है क्योंकि छठे, स्थान से द्वादश स्थान पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ती है अत: छठे स्थान में आया शुक्र धन के लिए शुभ होता है और भोग-विलास की वस्तुएं देता है।
4. ग्रह अपने भाव केन्द्रीय, त्रिकोण, पंचम, चतुर्थ, दशम हो तो शुभ होता है किंतु ग्रह का मित्र राशि में अथवा स्वग्रही अथवा उच्च होना अथवा वक्री होना अनिवार्य है सूर्य व मंगल को दशम भाव में, बुध व बृहस्पति को लग्न में, शुक्र व चंद्रमा को चतुर्थ में और शनि को सप्तम भाव में दिग्बल की प्राप्ति होती है।
5. चंद्र लग्न शरीर है और लग्न प्राण, इन दोनों का सम्मिलित विचार करके ही कुण्डली का फल करना चाहिए ग्रह अपना शुभ अथवा अशुभ फल अपनी महादशा में देते हैं महादशा व अंतर्दशा के ग्रह मित्र होकर एक दूसरे के भावों में जिसे ग्रहों का 'राशि परिवर्तन योग' कहते हैं होंगे तो अत्यंत शुभ फलदायक होंगे।
6. महादशा व अंतर्दशा के ग्रह एक दूसरे के शत्रु होंगे तो अशुभ फल की प्राप्ति होगी किसी भी ग्रह का उच्च का होकर वक्री होना उसकी शुभता में न्यूनता लाता है ग्रह का वक्री होकर उच्च होना अशुभता का सूचक है।
7. महादशा से अंतर्दशा का स्वामी ज्यादा बलवान होता है अत: अंतर्दशा का स्वामी शुभ हुआ और महादशा के ग्रह मित्र हुआ तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है यदि महादशा का स्वामी ग्रह महादशा का शत्रु हुआ और दोनों ग्रह एक-दूसरे से तृतीय, षष्ठम अष्टम अथवा द्वादश हुए तो महाअशुभ फलों की प्राप्ति समझनी चाहिए।

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत।।

फ्री ऑफर का जादू: लोग मुफ्त में कंघी भी ले लेंगे भले गंजे हों

--- संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल
[लेखक पिछले 18 वर्षों से वाणिज्य-अर्थशास्त्र के शिक्षक, वित्तीय एवं कर सलाहकार हैं]

"मुफ्त की चीज़ पर दिल फिदा,
जेब खाली हो जाए तो क्या हुआ।"

आज के उपभोक्ता व्यवहार को अगर एक लाइन में समझाना हो तो यही कहा जा सकता है कि "Free" शब्द सुनते ही आदमी की सोच का गणित बदल जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के सबसे पुराने और सबसे कारगर हथियारों में से एक है फ्री ऑफर। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि मनोविज्ञान का खेल है। ग्राहक को भले ही उस चीज़ की ज़रूरत न हो, लेकिन मुफ्त में मिल रही है तो उसे अपनाने की संभावना लगभग सौ प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

सोचिए, गली–मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े होकर अगर कोई कहे कि "फ्री सैंपल है, लीजिए" – तो क्या आप बिना देखे निकल जाएंगे? शायद नहीं। भले ही आपको उसकी ज़रूरत न हो, लेकिन दिमाग कहेगा – "चलो रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा।" यही है वह जादू जो फ्री ऑफर पैदा करता है। मनोविज्ञानियों का मानना है कि जब इंसान को कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो उसके दिमाग में "रिस्क अलार्म" का अलार्म बजता है। मतलब उसे लगता है कि कोई घाटा नहीं है, बस फायदा ही फायदा है। और यहीं से कंपनियां उपभोक्ता की इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती हैं।

भारत में ही देख लीजिए। मिठाई की दुकान हो या मोबाइल रिचार्ज, हर जगह "एक के साथ एक फ्री" का बोर्ड टंगा होता है। त्योहारों के सीज़न में तो जैसे "फ्री ऑफर" का बाढ़ आ जाता है – साबुन के साथ डिब्बा, बिस्कुट के पैकेट के साथ कप और टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश। मज़े की बात यह है कि ग्राहक अक्सर मूल चीज़ की क्वालिटी या कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि यह सोचकर संतुष्ट हो जाता है कि "कम से कम कुछ तो फ्री में मिल रहा है।"

फ्री ऑफर का यह जादू सिर्फ छोटे-मोटे सामान तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े ब्रांड भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। कार कंपनियां गाड़ी खरीदने पर मुफ्त सर्विस देती हैं, मोबाइल कंपनियां डाटा पैक पर मुफ्त एसएमएस देती हैं और ई-कॉमर्स कंपनियां तो "फ्री डिलीवरी" के नाम पर पूरा मार्केट जीत चुकी हैं। "फ्री डिलीवरी" असल में मुफ्त नहीं होती, उसका खर्च प्रोडक्ट की कीमत में पहले ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन ग्राहक के दिमाग में यह अहसास बैठ जाता है कि उसे कुछ फायदा हो रहा है। यहाँ तक कि डिजिटल युग में तो "फ्री" का जादू और भी गहरा हो गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल – ये सब अपने आप में मुफ्त सेवाएँ हैं। कोई इनसे पैसा नहीं लेता, लेकिन इसके बदले कंपनियां हमारे डेटा और ध्यान का कारोबार करती हैं। यानी असली कीमत हमसे ली जाती है, लेकिन हमें लगता है कि सबकुछ मुफ्त है। यही तो आधुनिक मार्केटिंग की सबसे बड़ी चाल है।

अगर इतिहास में जाएँ तो मुफ्त ऑफर का कांसेप्ट नया नहीं है। पुराने समय में भी हाट-बाज़ारों में दुकानदार मुफ्त में थोड़ी मात्रा में चीज़ चखने के लिए देते थे। जैसे मसाले बेचने वाला थोड़ा सा मसाला हाथ में रख देता था, ताकि ग्राहक उसकी खुशबू महसूस करके खरीद ले। मिठाई वाला ग्राहक को 'टेस्टिंग' के नाम पर छोटा टुकड़ा दे देता था। उस जमाने में इसे "मुफ्त चखना" कहते थे, आज इसे आधुनिक भाषा में "सैंपलिंग स्ट्रैटेजी" कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह स्थानीय स्तर पर होता था, अब यह एक ग्लोबल मार्केटिंग टूल बन चुका है। आज के जमाने में ग्राहक खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। वह सोचते हैं कि वह कंपनी की चाल को समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मार्केटिंग वालों का गणित हमेशा एक कदम आगे होता है। जब आप "एक के साथ एक फ्री" में प्रोडक्ट लेते हैं, तो अक्सर आपने उतना ही खर्च किया होता है जितना दोनों पर अलग-अलग करने पड़ता। कंपनियों को घाटा नहीं होता, बल्कि बिक्री बढ़ जाती है।

मजेदार बात यह है कि मुफ्त ऑफर से ग्राहकों में "खुशी का हार्मोन" भी एक्टिव हो जाता है। रिसर्च बताती है कि फ्री चीज़ मिलने पर इंसान के दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होता है, जो वैसा ही अहसास देता है जैसा लॉटरी जीतने या गिफ्ट मिलने पर होता है। यानी यह सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं बल्कि भावनात्मक संतुष्टि भी देता है। त्योहारों का उदाहरण लीजिए। दिवाली, होली, ईद या क्रिसमस – हर त्योहार में उपभोक्ता का मूड खर्च करने का होता है। ऐसे समय पर कंपनियां "फ्री ऑफर" को हथियार बनाकर खरीदारी को और बढ़ा देती हैं। ग्राहक जब गिफ्ट पैक या बोनस आइटम देखकर खरीदता है तो उसे लगता है कि उसने "स्मार्ट डिसीजन" लिया है, लेकिन असल में वह मार्केटिंग के जाल में फंस चुका होता है। फ्री ऑफर का असर इतना गहरा है कि कई बार लोग उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं। मान लीजिए किसी दुकान पर साबुन के साथ कटोरी फ्री मिल रही है। अब अगर ग्राहक के घर में पहले से ही पर्याप्त साबुन है, फिर भी वह अतिरिक्त साबुन खरीद लेगा सिर्फ उस कटोरी के लालच में। यही मनोविज्ञान कंपनियों के बिजनेस मॉडल को मजबूत करता है।

ऑनलाइन दुनिया में भी यही पैटर्न है। कई ऐप "फ्री ट्रायल" का विकल्प देते हैं। एक महीने मुफ्त में इस्तेमाल कीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाएगा। लोग पहले तो खुशी-खुशी "फ्री" का फायदा उठाते हैं, लेकिन बाद में जब ऑटो-डिडक्शन होता है तो पता चलता है कि मुफ्त में लिया गया ऑफर असल में कितना महंगा पड़ा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या यह फ्री ऑफर हमेशा ग्राहकों के लिए फायदे का सौदा होता है? इसका जवाब है – नहीं। कई बार मुफ्त ऑफर की वजह से लोग अपनी वास्तविक ज़रूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि ग्राहक "ज़रूरत" और "लालच" में फर्क समझे। दूसरी तरफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो यह रणनीति सबसे सफल है। यह न सिर्फ बिक्री बढ़ाती है, बल्कि ब्रांड की पहचान भी मजबूत करती है। ग्राहक जब बार-बार मुफ्त में प्रोडक्ट या सेवा अनुभव करता है, तो उसके मन में उस ब्रांड के प्रति भरोसा बढ़ता है। यही कारण है कि आज लगभग हर इंडस्ट्री – चाहे वह FMCG हो, टेक्नोलॉजी हो, या सर्विस सेक्टर – फ्री ऑफर को अपनी मार्केटिंग का अहम हिस्सा मानती है। भविष्य में यह ट्रेंड और भी बढ़ने वाला है। Artificial Intelligence और Data Analytics के ज़माने में कंपनियां ग्राहकों की पसंद-नापसंद को इतनी बारीकी से समझ पाएंगी कि हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग पर्सनलाइज्ड "फ्री ऑफर" डिज़ाइन किए जाएंगे। यानी गंजे को कंघी मुफ्त में नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए शायद शेविंग क्रीम या टोपी फ्री होगी।

यह समझना ज़रूरी है कि "फ्री ऑफर" की दुनिया असल में "Nothing is truly free" के सिद्धांत पर चलती है। कंपनियां हमेशा अपने खर्च की भरपाई कर लेती हैं। फर्क बस इतना है कि हम ग्राहकों को वह फालिक खुशी मिल जाती है कि हमने कुछ बिना दाम दिए हासिल किया। तो अगली बार जब आपको कोई कहे – "साबुन खरीदिए, बकेट फ्री पाइए" या "डेटा पैक लीजिए, कॉल फ्री पाइए" – तो एक बार सोचिए कि सच में क्या आप फ्री में ले रहे हैं, या फिर यह आपके ही पैसे का घूम-फिरकर खेल है। लेकिन हाँ, यह भी सच है कि मार्केटिंग की इस रंगीन दुनिया में "फ्री" शब्द सुनकर मुस्कुराना हर किसी को अच्छा लगता है। चाहे आप गंजे हों और कंघी आपके किसी काम की न हो, फिर भी अगर मुफ्त मिले तो दिल कहता है – "ले लो, क्या पता कभी काम आ ही जाए।"

निर्माण विभाग में रेत बजरी का खेल अरबों में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से विशेष जाँच एंव हस्तक्षेप की मांग- डॉ यादव

ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में निर्माण विभाग के अधीन ठेकेदारों व अधिकारीयों द्वारा रेत व बजरी के रॉयल्टी पेपर्स एवं संलग्न जीएसटी में बड़े पैमाने पर घोटाला - विभागीय तालमेल से अरबों रुपये की हानि

नई दिल्ली-₹उफ्तत्सा₹ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव की ओर से जारी यह प्रेस विज्ञप्ति विभिन्न राज्यों में रेत और बजरी खनन में हो रहे बड़े घोटाले को उजागर करती है। ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी के रूप में हमारी संस्था लंबे समय से परिवहन क्षेत्र में कार्यरत है और निर्माण सामग्री के परिवहन में ठेकेदारों एवं सरकारी विभागों के बीच हो रही अनियमितताओं को देख रही है। यह घोटाला न केवल राज्यों की राजस्व हानि का कारण बन रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंचा रहा है वहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) भी आंखें मूंदकर तमाशा देखने का कार्य कर रही है। हमारी जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि निर्माण विभाग के अधीन ठेकेदार रॉयल्टी पेपर्स में हेरफेर,प्रयुक्त किये गए समानों की जीएसटी चोरी व एक बील के जीएसटी कई और कार्यदेश में दिखाकर भुगतान लेना और अवैध खनन के माध्यम से अरबों रुपये का घोटाला लगातार बेधड़क कर रहे हैं, सभी रेत खनन क्षेत्र बजरी खनन क्षेत्र व अन्य खनन की जीपीएस द्वारा स्वतंत्रत सर्वे कराई जाए और एक उच्च स्तरीय जांच एजेंसी के द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं को खंगाला जाए जिसमें विभागीय अधिकारियों, परिवहन संस्थाओं का सीधा तालमेल शामिल हो।

घोटाले का तथ्यात्मक ब्योरा के तहत रेत और बजरी खनन भारत के कई राज्यों में एक बड़ा उद्योग है, जहां रॉयल्टी राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है (उदाहरण के लिए, बिहार में रेत पर प्रति घन मीटर 200-300 रुपये रॉयल्टी) और जीएसटी 5% की दर से लगता है। लेकिन ठेकेदारों द्वारा अवैध तरीके से खनन, कम रिपोर्टिंग और फर्जी बिलिंग के जरिए राजस्व की चोरी की जा रही है। कुल अनुमानित हानि अरबों रुपये में है, जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है -

बिहार में रेत खनन घोटाला मुख्य रूप से जुलाई 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बांका जिले में 131 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध रेत खनन घोटाले का खुलासा किया। यहां ठेकेदारों ने रॉयल्टी का भुगतान किए बिना नदियों से रेत निकाला और जीएसटी में चोरी की। ईडी ने राज्य सरकार से नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने अवैध खनन को अनदेखा किया। यह घोटाला 2023 से चल रहा है, जब ईडी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 250 करोड़ रुपये के अवैध खनन की जांच शुरू की थी, जिसमें रेत और बजरी शामिल थे। ठेकेदारों ने फर्जी परमिट और कम मात्रा प्रयुक्त कर दिखाकर रॉयल्टी बचाई, जबकि वास्तविक खनन कई गुना अधिक था जो आज भी बेधड़क जारी है।

झारखंड में जीएसटी और रॉयल्टी चोरी में विशेषरूप से जून 2025 में सीबीआई ने बिहार और झारखंड में 100 करोड़ रुपये के जीएसटी फ्रॉड पर छापेमारी की। हालांकि यह मुख्य रूप से टाइल्स और ऑटो पार्ट्स से जुड़ा था, लेकिन जांच में खनन क्षेत्र में समान पैटर्न ही पाया गया, जहां रेत और बजरी के ठेकेदार फर्जी इनवॉयस से जीएसटी चोरी कर रहे हैं। ईडी की 2023 की जांच में झारखंड में 250 करोड़ के अवैध खनन का खुलासा हुआ, जिसमें निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल थे, जो रॉयल्टी पेपर्स में हेरफेर कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे थे।

ओडिशा में अवैध पत्थर और रेत खनन के तहत अप्रैल 2025 में सीएजी ने ओडिशा में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर चोरी का खुलासा किया, जिसमें रॉयल्टी और जीएसटी की चोरी शामिल थी। मार्च 2021 में जीएसटी अधिकारियों ने भुवनेश्वर में छह खनन कंपनियों पर छापेमारी की, जहां रेत और बजरी के फर्जी बिल पाए गए। ठेकेदारों ने अनुमति से कई गुना अधिक खनन किया और विभागीय

तालमेल से रॉयल्टी कम दिखाई।आज भी सुंदरगढ़ जिले में अवैध रूप से सोलह नम्बर घाट, कुतरा, कंसर व अन्य रेत खनन व गुरुंडिया, सुंदरगढ़,सागजोर, राजगाँगपुर, कुआरमुंडा में बजरी खनन का कार्य बदस्तूर जारी है मुख्य रूप से ब्लास्टिंग पदार्थ की जांच करने पर भी कुछ हद तक नियंत्रण में लाई जा सकती है। विभिन्न टोलबूथों पर आवाजाही की जांच करने से अवैध रेत व बजरी की ढूलाई का सारा खाका खुलकर बाहर आ जाएगा व इससे जुड़े गाड़ियों को जब्त कर झारखंड की तर्ज पर नीलामी का प्रावधान होना चाहिए। अनुमानित हानि सैकड़ों करोड़ में है, जो विभिन्न खबर स्रोतों में वर्णित ओडिशा माइनिंग स्कैम से जुड़ी है, जहां रॉयल्टी 1948 से अपडेट नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में समान पैटर्न के अनुसार छत्तीसगढ़ में रेत खनन माफिया सक्रिय है, जहां ठेकेदार रॉयल्टी पेपर्स फर्जी बनाकर जीएसटी चोरी कर रहे हैं। 2023-2025 के बीच ईडी की जांच में पश्चिम बंगाल के साथ छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में 1100 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ, मुख्य रूप से खनन और रियल एस्टेट सेक्टर में। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन राजनीतिक विवाद का विषय रहा, जहां ठेकेदारों ने रॉयल्टी कम चुकाकर अरबों की चोरी की।

विभिन्न घटनाक्रम का क्रमः

2021-2023: जीएसटी अधिकारियों ने ओडिशा में खनन कंपनियों पर छापेमारी शुरू की, फर्जी बिलिंग उजागर हुई। बिहार-झारखंड में अवैध रेत खनन बढ़ा, माफिया ने विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत की।

जून 2023: ईडी ने बिहार, झारखंड में 250 करोड़ के अवैध खनन पर छापेमारी की, रॉयल्टी और जीएसटी चोरी पकड़ी गई।

2024: तमिलनाडु में समान घोटाले का खुलासा, लेकिन पैटर्न बिहार-ओडिशा से मिलता-जुलता।

जून 2025: सीबीआई की छापेमारी में 100 करोड़ जीएसटी फ्रॉड उजागर, खनन से जुड़े लिंक।

जुलाई 2025: ईडी ने बिहार में 131 करोड़ रेत घोटाले की रिपोर्ट दी, नई जांच की मांग।

सटीक आंकड़े:

कुल अनुमानित घोटाला: 1000-5000 करोड़ रुपये (बिहार: 131+250 करोड़, झारखंड: 250+100 करोड़, ओडिशा: सैकड़ों करोड़, छत्तीसगढ़: समान पैटर्न)।

रॉयल्टी चोरी: अनुमति से 10 गुना अधिक खनन, प्रति राज्य 50-100 करोड़ हानि वार्षिक।

जीएसटी चोरी: फर्जी इनवॉयस से 18-28% रिफंड क्लेम, कुल 1100 करोड़ यूपी में, समान अन्य राज्यों में।

पर्यावरण क्षति: नदियों का कटाव, बाढ़ जोखिम बढ़ा।

यह घोटाला विभागीय तालमेल से चल रहा है, जहां अधिकारी ठेकेदारों को फर्जी पेपर्स जारी करते हैं। ₹उफ्तत्सा₹ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) मांग करता है कि केंद्र सरकार सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों से जांच कराए, दोषियों पर कार्रवाई हो और ट्रक ट्रांसपोर्टरों को वैध परिवहन के पृष्ठभूमि सुनिश्चित किया जाए। हम ट्रांसपोर्टरों के हित में लड़ाई जारी रखेंगे।

डॉ. राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष
"उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा
(ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)

लालकिला मैदान में हुआ लव कुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन समारोह

मुख्य संवाददाता

देश की प्रख्यात लव कुश रामलीला कमेटी का भूमि पूजन समारोह भव्य रूप से लालकिला मैदान में संपन्न हुआ।

कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष का भव्य रामलीला मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा तथा दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा।

भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल के कर-कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा और दिल्ली के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना सम्पन्न की गई।

कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने सभी अतिथियों का पटका, स्मृति-चिन्ह और शक्ति का प्रतीक गदा भेंटकर सम्मान किया।

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा— "लव कुश रामलीला कमेटी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है। यह न केवल प्रभु श्रीराम की लीला का मंचन करती है, बल्कि सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों में भी सक्रिय है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रामलीलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। इसके लिए सभी परमिशन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा।"

अर्जुन कुमार ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामलीलाओं के लिए पुलिस लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करना और डीडीए द्वारा मेले हेतु 25–40% ग्राउंड का आवंटन, कलाकारों और आयोजकों के लिए बड़ी राहत है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष रामलीला हाईटेक डिजिटल मंचन के साथ होगी। लगभग 100 देशी-विदेशी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा। इस बार बॉलीवुड के लगभग 40 फिल्म कलाकार मंचन करेंगे।

कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने बताया कि इस अवसर पर बांसुरी स्वराज सांसद, योगेंद्र चंदोलिया सांसद, विजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा, अशोक गोयल देवरहा विधायक, अनिल शर्मा विधायक, पुरंदीप सिंह साहनी विधायक, पहलाद सिंह साहनी पूर्व विधायक, अनिल भारद्वाज पूर्व विधायक, अरविंद गर्ग जिला अध्यक्ष चांदनी चौक, पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

भूमि पूजन समारोह में कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य पवन गुप्ता, सत्यभूषण जैन, आरके गुप्ता, प्रवीण गोयल, संदीप भूटानी, गौरव गुप्ता, अंकुर गोयल, राजकुमार गुप्ता, गौरव सूरी, लोकेश बंसल, राजेश वर्मा, अनिल गुप्ता, अशोक कुमार, विशाल गुप्ता, राजकुमार कश्यप, संजय वर्मा, मदन अग्रवाल, प्रवीण सिंघल, अतुल गुप्ता, मुकुल गुप्ता, संजय जैन, प्रशांत मलिक, दीनानाथ सोनकर, सुनील कुमार, निशांत गुप्ता, राजा पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

श्री धार्मिक लीला कमेटी ने रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया

मुख्य संवाददाता

श्री धार्मिक लीला कमेटी दशहरा के अवसर पर माधवदास पार्क, लालकिला मैदान पुरानी लाजपत राय मार्केट के सामने में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी रामलीला मंचन कराने के लिए रविवार को भूमि पूजन किया। भूमि पूजन श्री जानकी मंदिर जनकपुर नेपाल के महंत राम रोशन दास ने किया।

भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी व मीरा कुमार, सांसद योगेंद्र चांदोलियो के अलावा फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह रामलीला में हनुमान की भूमिका निभाएंगे, अभिनेता अरबाज खान रामलीला में रावण की भूमिका निभाएंगे, अभिनेत्री शिल्पा रायजादा, सीता की भूमिका निभाएंगी,

बड़ी संख्या में अनेक नेताओं ने भगवान राम के दरबार की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन सुरेश गोयल, महासचिव **धीरजधर गुता एवं सचिव प्रदीप शरण, कमेटी के प्रवक्ता रवि जैन ने**

सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। कमेटी ने रामलीला मंचन करते हुए 100 वर्ष गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नेताओं ने कहा कि रामलीला मंचन कराना एक सराहनी कदम है। रामलीला मंचन देखकर हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है और हम उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने घर, परिवार, इलाके एवं देश का कल्याण करने का प्रयास करते है। इसके अलावा अपने माता-पिता का सम्मान और बच्चों को प्यार करने मंत्र मिलता है। उन्होंने बताया कि वहीं युवा पीढ़ी देश की संस्कृति से रूबरू होती है और उसे अपना लक्ष्य तय करने और उसे प्राप्त करने में मदद मिलती है। रामलीला मंचन से बुराइयों से दूरी बनती है और सत्य के मार्ग पर चलने मन करता है।

भगवान श्रीराम के पावन चरित्र का मंचन समाज में मर्यादा, सत्य और आदर्श मूल्यों को स्थापित करता है

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज अनेक रामलीला कमेटियों द्वारा आयोजित भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए।

रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के 'रामलीला' भूमि पूजन कार्यक्रम में वीरेन्द्र सचदेवा के साथ केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित थे। इसके अलावा श्री धार्मिक लीला कमेटी, माधवदास पार्क 'रामलीला' लाल कीला के भूमि पूजन समारोह में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग भी शामिल हुए।

वीरेन्द्र सचदेवा ने इस मौके पर कहा कि रामलीला समाज में भक्ति, नैतिकता और संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित करती है। भगवान श्रीराम के पावन चरित्र का मंचन समाज में मर्यादा, सत्य और आदर्श मूल्यों को स्थापित करता है और उसका साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आज के समाज में जहां सब कुछ कमर्शियल हो गया है, वहां रामलीला एक ऐसा माध्यम है जो जन-जन तक भगवान की भक्तिमय बातों को पहुंचाने का काम करता है।

सचदेवा ने कहा कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़ा एक गहरा, भावनात्मक और प्रेमपूर्ण संबंध है जो जाति, धर्म या भाषा की सीमाओं से परे होता है।

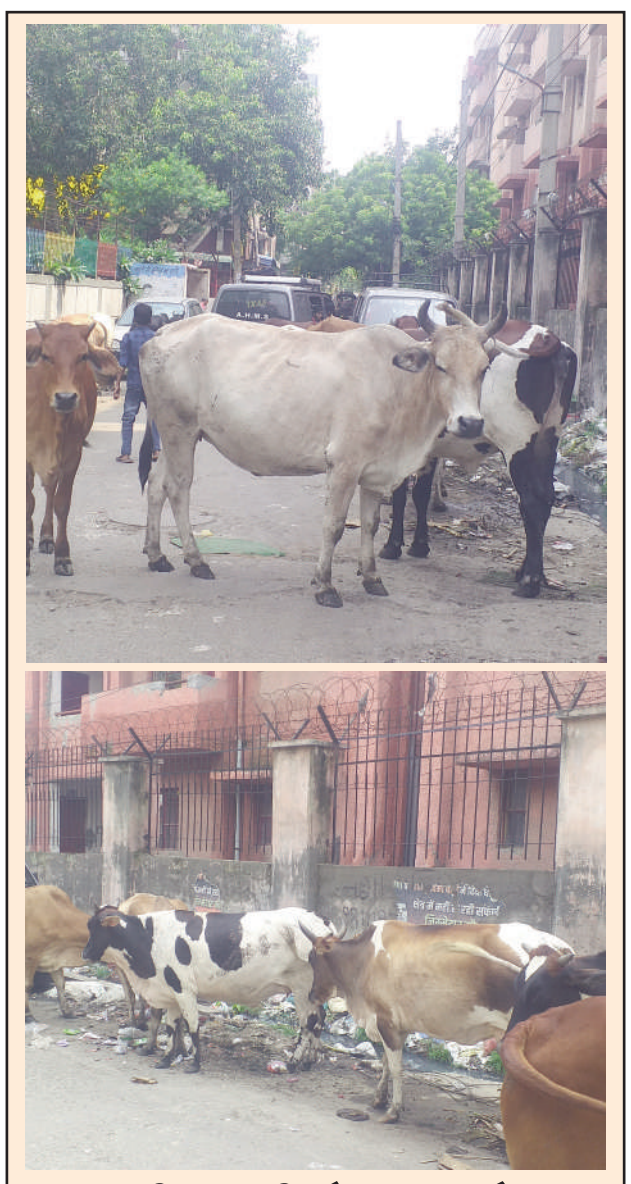

जहांगीर पुरी में सड़को पर पशुओं का जमावड़ा, लोग हो रहे है परेशान: भास्कर

- आरडब्ल्यूए ने सीएम से लगाई गुहार, उचित हो कार्रवाई, ताकि जनता को मिले समस्या से राहत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पशुओं का सड़क व रोड़ पर जमावड़ा होने की वजह से जनता को समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशान होना पड़ता है।

कुछ ऐसा ही हाले पिछले कई महिनों से जहांगीरपुरी के आई और जे ब्लॉक में बना हुआ है। पशुओं की वजह से आये दिन जहां एक ओर रोड़ पर हादसे हो रहे है, वही दोपहिया वाहन वाले रोड़ों पर पशुओं की वजह से चोटिल हो रहे है। लेकिन प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है।

इस समस्या पर बोलते हुए जहांगीरपुरी आई एण्ड जे ब्लॉक आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एमएल भास्कर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की लापरवाही की वजह से पशु सड़कों व गलियों में नजर आ रहे है, अगर प्रशासन गंभीरता से कार्य करते हुए अगर इन पशु मलिको पर कार्रवाई करें तो इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है।

जहांगीरपुरी आई एण्ड जे ब्लॉक आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष एमएल भास्कर ने दिल्ली की सीएम और सिविल लाईन जोन के डीसी से गुहार लगाते हुए कहा कि इस समस्या पर आप गौर करें, जिससे की जनता को उपरोक्त समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि आप इन पशु मलिको पर नियमानुसार कार्रवाई करें, जिससे की जो भी पशु मलिक है, वह पशुओं को गली व सड़को पर घूमने के लिए न छोडे। श्री भास्कर ने बताया कि कई बार इन पशुओं की वजह से दोपहिया वाहन चालक और बच्चे चोटिल भी चुके है, लेकिन इस समस्या को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है।

446 ग्राम ड्रग के साथ पुलिस ने बुराड़ी से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली: उपराज्यपाल, दिल्ली के निर्देशानुसार, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा नशामुक्त दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशे के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अनुरूप, दिनांक 19.08.2025 को, सहायक पुलिस आयुक्त श्री नरेन्द्र बेनीवाल के पर्यवेक्षण और निरीक्षक संदीप स्वामी के नेतृत्व में, एनआर-II, अपराध शाखा की एक समर्पित टीम ने, कुख्यात नशा तस्कर, सौरव उर्फ आर्यन, पुत्र तालिक राम, निवासी रेखा सिन्हा का मकान, हरदेव नगर, बुराड़ी, दिल्ली, उम्र 29 वर्ष, को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया।

इस कार्रवाई के दौरान, उसके कब्जे से लगभग 446 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली स्मैक/हेरोइन (व्यावसायिक मात्रा में) जब्त की गई, जो ड्रग तस्करी के उन्मूलन के लिए अपराध शाखा के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है। तदनुसार, दिल्ली पुलिस थाना, अपराध शाखा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत एफआईआर संख्या 219/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों और नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को प्राप्त करने के स्पष्ट आदेश के साथ, एनआर-II, अपराध शाखा की टीम को दिल्ली में सक्रिय ड्रग तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैनात किया गया था। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, 19.08.2025 को, प्रधान सिपाही राज आर्यन द्वारा प्रदान की गई कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर, निरीक्षक संदीप स्वामी के नेतृत्व में एनआर-II टीम द्वारा छापा मारा गया, जिसमें उप निरीक्षक प्रदीप दहिया, उप निरीक्षक सुखविंदर, सहायक उप निरीक्षक सुनील, प्रधान सिपाही सुमित, प्रधान सिपाही नवल, प्रधान सिपाही राज आर्यन, महिला प्रधान सिपाही सीमा और सिपाही योगेंद्र शामिल थे। यह छापेमारी सहायक पुलिस आयुक्त/एनआर-II श्री नरेंद्र सिंह बेनीवाल के निकट पर्यवेक्षण और उपायुक्त पुलिस/अपराध शाखा श्री हर्ष इंदौरा, भा.पु.से. के मार्गदर्शन में की गई।

इस अभियान के परिणामस्वरूप सौरव उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 446 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली स्मैक/हेरोइन बरामद की गई। इसके बाद, थाना अपराध शाखा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत एफआईआर संख्या 219/25 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जाँच के दौरान, 21.08.2025 को, अपराध शाखा की टीम ने ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ करते हुए इसकी सरगना, सुरेखा उर्फ शन्नो, पत्नी कमल कुमार, निवासी ए-616, जे.जे. कॉलोनी, हस्तल रोड, उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र 40 वर्ष, को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान उसके सहयोगी सौरव उर्फ आर्यन से जब्त 446 ग्राम स्मैक/हेरोइन की मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में हुई, जिसे 19.08.2025 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

सौरव उर्फ आर्यन (उम्र 28): सातवीं कक्षा तक पढ़ा है। वह पहले मंगोलपुरी में कई स्नैचिंग के मामलों में और बाद में सागरपुर और किराड़ी में अवैध शराब के धंधे में शामिल रहा है। शादी के बाद, उसने उत्तम नगर में ऑटो-रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। लगभग 5-6 महीने पहले, वह शन्नो के संपर्क में आया, जिसने उसे बेहतर कमाई के लिए स्मैक बेचने के लिए राजी किया। वह मान गया और उससे नियमित रूप से ड्रग्स खरीदने लगा। सुरेखा उर्फ़ शन्नो (उम्र 52): पाँचवीं कक्षा तक पढ़ी है। पहले अवैध शराब, गांजा और चरस बेचने में शामिल थी और कई बार गिरफ्तार भी हुई थी। 2018 से, वह उत्तम नगर में चोरी-छिपे शराब बेच रही थी। 2022 में, उसने पैकेट में स्मैक बेचना शुरू कर दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जेल से रिहा होने के बाद, उसने अपने बेटे आकाश के साथ मिलकर सौरव को बड़ी मात्रा में स्मैक बेचना फिर से शुरू कर दिया। उसने एक स्थानीय चिटफंड समिति के माध्यम से सौरव को इस धंधे में शामिल किया।

टैरिफ नीति से नए 'ग्लोबल ट्रेड' का उदय ?

प्रभुनाथ शुक्ल

अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने 'ग्लोबल ट्रेड' को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका की यह आर्थिक नीति दुनिया को कहां ले जाएगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खुद अमेरिका के लिए यह आर्थिक और सामरिक संबंधों पर कितनी कारगर होगी, यह वक्त बताएगा। ट्रंप इस आर्थिक नीति से अमेरिका को कितना समृद्ध कर पाते हैं, यह देखना होगा लेकिन ट्रंप की दादागिरी ने ग्लोबल ट्रेड नीति को बड़ा झटका दिया है। अत्यधिक टैरिफ की मार झेल रहे भारत, चीन और रूस जैसे देश नई व्यापार नीति को अंजाम देने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। यह दक्षिण एशिया के लिए जहाँ सुखद है, दूसरी तरफ अमेरिका के भविष्य के लिए चिंतनीय।

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की टैरिफ़ नीति को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद ट्रंम्प को बड़ा झटका लगा है। सरकार और अदालत के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। यह ट्रंप की विदेश नीति के खिलाफ बड़ा फैसला है। अदालत ने ट्रंम्प प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया है. सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दुनिया के देशों के लिए यह सुखद फैसला है क्योंकि अमेरिका में खुद ट्रंप अपनी आर्थिक नीति की आलोचना झेल रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत के फैसले के बाद ट्रंप विरोधी और मजबूत होंगे।

अमेरिका की इस पॉलिसी से भारत जैसे देश उसके खिलाफ हो गए। जिस चीन को सबक सिखाने के लिए वह भारत के साथ खड़ा था। वहीं चीन और भारत अब अमेरिकी नीति के खिलाफ एक मंच पर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया की दो महाशक्तियां एक मंच पर आ रही है तो ट्रेड वॉर में कुछ नया होने वाला है जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन की खास भूमिका है। इसका बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ आर्थिक नीतियों पर ही नहीं, ग्लोबल वार, हथियार की होड़ और आर्थिक नीति पर भी पड़ेगा। ट्रंप के आगे भारत के ना झुकने की पॉलिसी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है।

दुनिया में सबसे अधिक भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप की यह नीति आर्थिक रूप से भारत की कमर तोड़ने की साजिश है। ट्रंम्प भारत को झुकाना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरह खुद का पिछलग्गू बनाना चाहते हैं लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है। भारत की दुनिया में एक साख है। उसके पास विपुल आबादी है। कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था उसका बेहद मजबूत आधार है। ऐसे हालात में भुखमरी के हालात बनने से रहे, आर्थिक नुकसान भले उठाना पड़े। फिर भारत क्यों झुकेगा।

आर्थिक विश्लेषण और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय निर्यात पर काफी असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल, कृषि उत्पादन, आर्नामेंट, चमड़ा, फुटवियर, केमिकल्स और मेडिसिन बाजार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत से करीब 28 फीसदी वस्त्र, कालीन का निर्यात अमेरिका को होता है। भारत के संपूर्ण व्यापार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 20 फीसदी है। भारत की जीडीपी में दो फीसदी योगदान है। यह माना जा रहा है कि भारत को अरबों डालर का नुकसान होगा लेकिन क्या अमेरिका के सामने भारत का झुकना भी ठीक है। समस्याएं आती हैं तो हमें विकल्प भी तलाशना होगा जिसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में भारत जुटा है।

हालांकि ट्रंप की वजह से भारत में नौकरियां जाने का भी खतरा बना है। कई लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। श्रमप्रधान सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान का प्रभाव दिख सकता है। टेक्सटाइल, आभूषण, कृषि रत्न जैसे सेक्टर में यह स्थिति दिखाई देगी। केंद्र की मोदी सरकार इससे से निपटने के लिए रणनीति भी बना रही है। फिर भी अगर अमेरिका के साथ बीच में कोई समझौता न हुआ तो भारत को आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ेगा। भारत को अब हर हाल में अमेरिका पर निर्भरता कम करनी होगी।

प्रधानमंत्री का जापान, इसके बाद चीन दौरा इसका संकेत है। वहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कुछ नया गुल खिलाएगी। ग्लोबल ट्रेड पर कोई नया फैसला हो सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बन सकती है। अगर तीनों देशों की तिकड़ी सफल हो गई तो भविष्य में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैरिफ़ नीति को अंजाम दिया लेकिन उसकी इस पॉलिसी में साफ-सुथरी आर्थिक दृष्टि नहीं दिखती। अमेरिका की इस पॉलिसी में ग्लोबल पॉलिटिक्स की गंध आती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी भूमिका खारिज कर दी तो वह चिढ़ गया। भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो उसका हित टकरा गया। उसने चीन के खिलाफ जहां 30 फ़ीसदी टैरिफ लगाया , वहीं भारत के खिलाफ 50 फीसदी। यह ट्रंप की पारदर्शी टैरिफ़ नीति नहीं है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपनी खींझ और गुस्से का प्रदर्शन किया है लेकिन भारत भी अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है।

भारत समेत ब्रिक्स संगठन में शामिल देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। संगठन में भारत सबसे अग्रणी है । अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों में टैरिफ कम करें लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया जिसका नतीजा हुआ ट्रंप ने टैरिफ बम भारत पर फोड़ दिया।

हालांकि इसका दुष्प्रभाव एक पक्षीय नहीं होगा। यह अलग बात है कि भारत को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा लेकिन ट्रंप की इस टैरिफ नीति ने भारत के साथ दुनिया के देशों को एक कड़ा संदेश दिया है। संदेश साफ है कि पर सबसे अधिक आत्मनिर्भरता को हर हाल में खत्म या कम करना होगा। व्यापार नीति में बदलाव लाना होगा।

हालांकि अमेरिका ने जो आर्थिक जंग छेड़ी है उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसका असर सिर्फ व्यापार क्षेत्र में ही नहीं पड़ेगा। सामरिक संबंधों और वैश्विक कूटनीति पर भी दिखेगा जिसके बाद एक ग्लोबल स्तर पर तनाव की स्थिति बनेगी। दुनिया को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के शताब्दी संदेश से बहुत कुछ प्रेरणा ले सकती है भाजपा

कमलेश पांडेय

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब भी कुछ बोलते हैं उसे बिना कुछ सोचे समझे देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित मान लिया जाता रहा है। ऐसे में इस बार भी उन्होंने विज्ञान भवन में जो कुछ कहा है, उसे बीजेपी से ही जोड़कर देखा ही जाएगा। सर्वप्रथम, उनका यह कहना महत्वपूर्ण है कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई लेना-देना नहीं', बल्कि इसके बड़े मायने हैं। ऐसे समय में जब देश में हिंदूवादी राजनीति अपने शिखर पर है, मोहन भागवत द्वारा दिया गया यह भाषण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

वाकई जब वे कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं है, तो इसके गहरे सियासी निहितार्थ हैं। क्योंकि प्रायः भाजपा सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि वह इस विचारधारा को सत्ता पाने और उसमें बने रहने के औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। कहना न होगा कि संघ बीजेपी को समय समय पर वैचारिक खुराक व प्रबुद्ध दिशानिर्देश देता रहा है। यही वजह है कि अपने तमाम मतभेदों के बावजूद संघ और बीजेपी एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं।

ऐसे में स्पष्ट है कि भागवत का कथन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि संघ की मूल वैचारिक धारा की वह सहज और सरल अभिव्यक्ति है, जो देश में सत्तासीन बीजेपी नीत एनडीए सरकार के लिए एक माकूल दिशा का निर्धारण भी करता है। ऐसे में सीधा सवाल यह है कि संघ प्रमुख के इस बयान के मायने क्या हैं? क्या यह सीधे-सीधे वक्त-वेवक्त लीक से भटकती दिखाई देतीबीजेपी नेताओं को संदेश देता है?

यूँ तो 21वीं सदी के महान किंगमेकर मोहन भागवत समय समय पर नीतिगत बातें स्पष्ट करते रहते हैं। ऐसे में उनका यह ताज़ा बयान भी ऐसे समय पर आया है जब इंडिया गठबंधन रूपी बिखरा विपक्ष भाजपा पर निरंतर यह आरोप मढ रहा है कि वह बहुसंख्यकवाद और ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनकी दूरदर्शिता के बदौलत ही भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्तासीन है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी उसके हाथ में सूबाई सत्ता की ताकत है।

लिहाजा, संघ प्रमुख का यह कहना कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ सत्ता से नहीं है, एक राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद के रूप में भी देखा जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि संघ अब बीजेपी को हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को थोड़ा नरम करके चलने का संकेत देना चाहता हो। चूंकि परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए संघ की सोच-समझ में समयानुसार नीतिगत सुधार अपेक्षित है। ऐसे में जो आरएसएस अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों से ही हिंदू राष्ट्र की बात पर मुखर रहा है, वह भी नरम हो रहा है।

बता दें कि सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें गुरुजी कहा जाता है, ने इसे परिभाषित करते हुए कहा था कि भारत की आत्मा हिंदू है और यहां की संस्कृति की जड़ें हिंदुत्व से निकली हैं। वाकई संघ का शुरू से ही मानना रहा है कि हिंदू शब्द सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि इसमें सभ्यता, परंपरा, जीवनशैली और सामाजिक मूल्य सभी शामिल हैं। यही वजह है कि संघ हमेशा कहता रहा कि मुसलमान, ईसाई, पारसी या अन्य धार्मिक समूह भी इस राष्ट्र के उतने ही हिस्से हैं, जितने हिंदू। इसलिए यह बिल्कुल सीधा और साफ संदेश है कि भागवत का बयान संघ की पुरानी लाइन को ही दोहराता है।

कहना न होगा कि आरएसएस सीधे सत्ता की राजनीति में शामिल नहीं होता है, बल्कि संघ की असली ताकत समाज-निर्माण, जनशिक्षा, जनसेवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में है। इसलिए संघ प्रमुख के इस बात में कुछ भी नया नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य संसद में बहुमत पाना नहीं है, बल्कि समाज को ऐसा बनाना है जिसमें नैतिकता, समरसता और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो। लेकिन उनकी इस बा त

की टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यह हो सकता है कि संघ प्रमुख बीजेपी के लिए कोई सीमा रेखा खींच रहे हैं या अल्पसंख्यकों को कोई व्यापक संदेश दे रहे हों।

ऐसा इसलिए कि भारत में हिंदू राष्ट्र का सीधा संबंध अक्सर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना से लिया जाता है। जबकि विपक्ष इसे बहुसंख्यकवादी एजेंडा मानता है। वहीं, चूंकि कांग्रेस-समाजवादियों की तुष्टीकरण की नीतियों से ही हिंदुओं को काफी क्षति हुई है, जिससे संघ-भाजपा की विचारधारा को मजबूती मिली। हालांकि, कांग्रेस नेताओं के मुंह से बीजेपी के बजाय आरएसएस के लिए ज्यादा अपशब्द निकलता रहा है। वहीं आरएसएस के मुख से नेहरू-गांधी परिवार की कुचक्री नीतियों के लिए। शायद यही कारण है कि जब भागवत कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई संबंध नहीं है तो यह संदेश जाता है कि संघ का उद्देश्य किसी पर वर्चस्व थोपना नहीं है, बल्कि यह अवधारणा सबको साथ लेकर चलने वाली सांस्कृतिक पहचान की है।

यहां पर समझने वाला आवश्यक तथ्य यह है कि आखिर संघ यह बात बार-बार क्यों दुहरा रहा है? क्या वो भाजपा के स्थायी शासन के लिए अल्पसंख्यकों को रिझाना चहता है? या फिर यह कहीं बीजेपी को अगले विधानसभा चुनावों के लिए इशारा तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष बिहार और अगले वर्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में डेमोग्रेफी चेंज और मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अल्पसंख्यकों पर लगातार जुबानी हमले कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि संघ यह चाहता हो कि बीजेपी को अपने रुख में थोड़ी नरमी लानी चाहिए !

वहीं, भागवत का बयान भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से यह याद दिलाता है कि संघ की दृष्टि सत्ता से आगे की है। भाजपा हिंदू राष्ट्र को राजनीतिक नारे के रूप में इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए कर सकती है। लेकिन भागवत का यह बयान केवल वैचारिक नहीं बल्कि जमीनी राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। क्योंकि बार-बार यह सवाल उठ रहा है कि देश में बेरोजगारी, किसान संकट जैसे मुद्दे हिंदू-मुसलमान की राजनीति के चलते गौण हो गए हैं। लिहाजा, संघ शायद यह संदेश देना चाहता है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ इन समस्याओं से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि इन्हें समाज-आधारित समाधान देना है।

कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक

पीड़ितों के पक्ष में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का पर्याय कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां आठ जिलों कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज, फतेहगढ़, जालौन, ललितपुर और झांसी के अधिकार क्षेत्र वाली कानपुर जोन अपराधियों के खिलाफ कानून और शांति व्यवस्था के पक्ष में हर दृष्टिकोण से अव्वल चल रही है। मामला चाहे घटनाओं के सटीक खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी का हो या फिर जन समस्याओं के निस्तारण से संबंधित आईजीआरएस का।

अवगत कराते चलें कि आजकल एडीजी के रूप में कानपुर जोन की कमान योगी सरकार की मंशा के अनुरूप अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और पीड़ितों की सहायता में भी सदैव अव्वल राष्ट्रपति तक के गोल्ड और प्लेटिनम समेत सभी तरह के मेडलों और पुरस्कारों के रुप में अनेक दुर्लभ उपलब्धियों के प्रसंसनीय धारक नोएडा के पहले सफल और सर्वोत्तम पुलिस कमिश्नर भी रहे भारत के कर्तव्यनिष्ठ और इमानदार आईपीएस अधिकारियों में से एक वरिष्ठ आई पी एस आलोक सिंह के हाथ में है।

सराहनीय और अनुकरणीय कार्यशैली वाले व्यवहार कुशलता के भी धनी, शिवत्व स्वभाव के भी माने जाने वाले सुप्रसिद्ध वरिष्ठ आईपीएस एडीजी आलोक सिंह का अबतक का जुझारू इतिहास यह साबित करता है कि उनकी कर्तव्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा हर छोटी से छोटी घटना को भी बहुत गम्भीरता से लेकर पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाही और पीड़ितों की सहायता में भी सदैव अग्रणी रही है। उनके पास जो भी जाता है। वह निराश नहीं लौटता। जहां तक कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सफलता का सवाल है। कानपुर जोन के भगवान और भाग्य यानी कम भरोसे रहने वाले जुझारू एडीजी आलोक सिंह की नेतृत्व कुशलता योगी सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित में हर दृष्टिकोण से सफल ही साबित हुई है ,क्योंकि ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को विश्वास है कि संसार संचालक ईश्वर समय आने पर अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही देता है। और वह इसके लिए जिन्हें अपना माध्यम बनाता है। आलोक सिंह जैसा वह जनहित में अपना कर्तव्य भी संपूर्ण ही निभाता है। कुल मिलाकर जनहित में विशुद्ध ईमानदारी का नाम आलोक है। दबाव में नहीं झुकने वाली निडरता का नाम भी आलोक है। पीड़ितों की हर संभव सहायता करने की मंशा का नाम आलोक है। अपराधियों के उनके कर्मों का फल देने की कर्तव्य निष्ठा का नाम आलोक है। वही आलोक जो प्रकाश का भी पर्याय है और वही प्रकाश जिसके दायरे में आने वाला कोई अपराधी बच नहीं पाता है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब जन्म धरती पर। मृत्यु धरती पर। और सारे अच्छे-बुरे कर्म धरती पर, तो फिर इंसान उनका फल भी आसमान में नहीं धरती पर ही पाता हैं ,जिसके लिए ही परमेश्वर योगी ,मोदी ही नहीं आई पी एस आलोक सिंह भी बन जाता है।

शरणागति सुगम है और श्रेष्ठ भी है परंतु इसमें एक कठिनाई है। जब तक व्यक्ति अपने-आपको कुछ/बहुत कुछ मानता है कि "मैं करता हूँ", तब तक उसमें प्रेम प्रकट नहीं होता।

जिस प्रेम में जीव की भगवान् के साथ एकता/ऐक्य स्थापित हो जाती है। जैसे एक कन्या पीहर को छोड़कर, विवाह के बाद पति के साथ एक हो जाती है, ऐसे ही भक्त संसार को छोड़कर, भगवान् के साथ एक हो जाता है। परंतु संसार के छूटने में एक विलक्षणता है इसमें संसार की जड़ता मिट जाती है और अंश की चिन्मयता रह जाती है। जैसे, मीराबाई का शरीर वहीं रह गया लेकिन मीरा का अंश चिन्मय होकर भगवान् के श्रीविग्रह में लीन हो गया। ज्ञान में बोध होने पर शरीर अलग रहता है, अंश/आत्म चिन्मय हो जाता है। ध्यान रहे कि भक्त के लिये समस्त संसारमात्र चिन्मय हो जाता है और एक सच्चिदानन्द परमात्म ही रह जाता है। परमात्म में पशु, पक्षी, वृक्ष, मकान, दीवार आदि जो कुछ है, सब-का-सब चिन्मय है। जैसे यहाँ संसार में सब कुछ जड़ है, ऐसे ही परमात्म में सब कुछ चेतन है, चिन्मय है, ज्ञानस्वरूप है, परमात्मस्वरूप है। ऐसी विलक्षण अनुभूति, ऐसा आनन्द शरणागति से ही प्राप्त होता है।

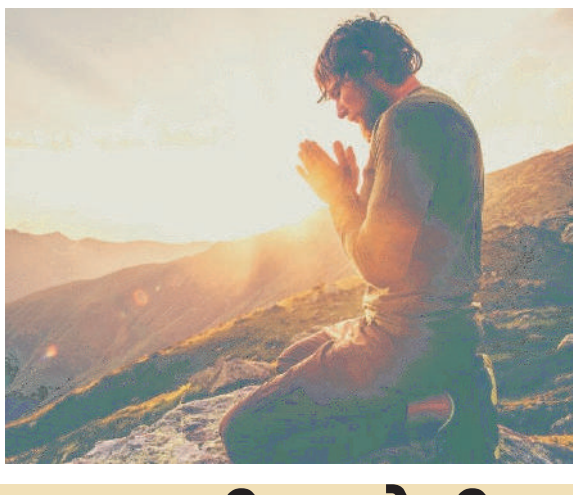

विवाह समारोह-पवित्र संस्कार ,आधुनिकता का दंश और समाज की चुनौती
शादी समारोहों में शराब, डीजे, नाइट पार्टी और वेस्टर्न कल्चर की नकल आम हो गई है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में शादी केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार मानी जाती है। वेदों से लेकर पुराणों तक, गृहस्थ जीवन को धर्म का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। विवाह को केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों और दो कुलों का मिलन माना जाता है। इसीलिए इसे सात फेरे, सप्तपदी मंत्र, कन्यादान, होम, आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सम्पन्न कराया जाता है। किंतु आज बदलते समय में विवाह के स्वरूप में गहरा बदलाव दिखाई दे रहा है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि शादी समारोह, जो कभी अध्यात्म, त्याग, संस्कार और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक था, अब धीरे-धीरे दिखावे, पैसे की होड़, दहेज, शराब और भव्यता की दौड़ में सिमटता जा रहा है। यह बदलाव न केवल भारतीय संस्कृति के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सामने एक विकृत परंपरा स्थापित कर रहा है। इस विषय का विस्तार से डिस्कशन व विश्लेषण हम 5 प्वाइंटों के आधार पर करेंगे।

साथियों बात अगर हम विवाह एक पवित्र संस्कारः आध्यात्मिक और सामाजिक आयाम की करें तो, भारतीय संस्कृति में विवाह को सोलह संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना गया है। यह केवल पति-पत्नी के शारीरिक या भावनात्मक संबंध का बंधन नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना का आधार है। विवाह का उद्देश्य केवल जीवनसाथी चुनना नहीं, बल्कि समाज में संतुलित, संस्कारित और धार्मिक जीवन की स्थापना करना है। सात फेरे, जिन्हें हर दंपति विवाह के समय अग्नि के साक्षी में लेता है, केवल शब्द नहीं हैं बल्कि जीवन के लिए आजीवन वचन हैं।आज की पीढ़ी इन मंत्रों और वचनों की गहराई को समझे बिना केवल विवाह को "सोशल इवेंट" की तरह देखने लगी है। होटल, रिजॉर्ट, फार्महाउस और डेस्टिनेशन वेडिंग ने विवाह को पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी के बजाय लक्ज़री इवेंट में बदल दिया है। यह बदलाव भारतीय समाज की मूल आत्मा के विपरीत है।

साथियों बात अगर हम आधुनिकता का दंश और बदलती शादी की परंपरा व दहेज और उपभोक्तावादी संस्कृति की करें तो आधुनिकता अपने साथ तकनीकी विकास, वैश्विक संपर्क और नए अवसर लाती है, परंतु इसका अंधानुकरण विवाह जैसे संस्कारों को विकृत कर रहा है। आज शादियाँ अधिकतर स्टेटस सिंबल बन गई हैं।(अ) लाखों- करोड़ों रुपए खर्च कर "शाही शादी" दिखाना अब फैशन बन चुका है। (ब) शादी समारोहों में शराब, डीजे, नाइट पार्टी और वेस्टर्न कल्चर की नकल आम हो गई है। (क़) रिश्तेदारों और मेहमानों का सम्मान अब मेन्यू की विविधता और सजावट की भव्यता से आंका जाने लगा है, न कि आत्मीयता और आदर से।इस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने विवाह की पवित्रता को गहरे तक प्रभावित किया है। जहां कभी विवाह का

अर्थ "दो आत्माओं का आध्यात्मिक बंधन" था, वहीं आज विवाह का अर्थ "सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो" बन गया है।दहेज और उपभोक्तावादी संस्कृति-विवाह का कुरूप चेहराः-दहेज प्रथा भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद से लगातार प्रयासों के बावजूद यह कुरीति खत्म नहीं हुई। आधुनिकता और भौतिकतावाद ने इसे और मजबूत कर दिया है। आज शादी समारोह में गाड़ियों की डिमांड, महंगे गिफ्ट्स, कैश और प्रॉपर्टी की अपेक्षा खुलेआम की जाती है।दहेज न केवल विवाह के पवित्र बंधन को कलंकित करता है बल्कि यह महिलाओं के लिए अपमानजनक और अमानवीय स्थिति पैदा करता है। हजारों बेटियाँ आज भी दहेज के बोझ के कारण या तो शादी नहीं कर पातीं या शादी के बाद उत्पीड़न का शिकार होती हैं।

साथियों बात अगर हम विवाह और शराब संस्कृति, के तेजी से बढ़ते प्रचलन की करें तो, भारतीय समाज में विवाह हमेशा से संयम, मर्यादा और उत्सव का संगम रहा है। परंतु पिछले दो दशकों में शादियों में शराब की संस्कृति तेजी से फैली है। यह न केवल समारोह की गरिमा को कम करता है बल्कि कई बार हिंसा, विवाद और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है।आज समाज के सामने यह प्रश्न है कि क्या विवाह का उत्सव बिना शराब, नाच-गाने और दिखावे के संभव नहीं? विवाह जैसे पवित्र अवसर पर यदि आत्मसंयम और मर्यादा खो जाए तो वह केवल मनोरंजन बनकर रह जाता है।

साथियों बात अगर हम विवाह में बढ़ता दिखावापन और समाज पर असर की करें तो,₹शादी में कितना खर्च हुआ?" यह प्रश्न आज समाज का सबसे बड़ा मूल्यांकन बन गया है। किसी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा अब शादी की भव्यता से तय होती है। परिणामस्वरूप गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार कर्ज, उधार और आर्थिक बोझ तले दब जाते हैं। (अ) शादियों में करोड़ों का खर्च करना "प्रेस्टीज इश्यू" बन चुका है। (ब) आम परिवार इस दौड़ में शामिल होने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर देते हैं। (क़) और छोटे कस्बों में भी यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे आर्थिक असमानता और बढ़ रही है।यह प्रवृत्ति भारतीय समाज के लिए खतरनाक है क्योंकि इससे सामाजिक संतुलन और समानता की अवधारणा को गहरी चोट पहुंचती है।

साथियों बात अगर हम घटते पारंपरिक संस्कार और अनुष्ठान की करें तो पहले विवाह घर-आंगन में, मंदिरों या पंचायतों में पूरे परिवार और समाज की सहभागिता से होते थे। बारात में ढोल-नगाड़े, लोकगीत, नृत्य, भजन- कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व होता था। परंतु अब इनकी जगह डीजे, फिल्मी गाने और कोरियोग्राफ्ड डांस ने ले ली है।कन्यादान, होम, सप्तपदी, वरमाला जैसे संस्कार केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं।कई बार डेस्टिनेशनवेडिंग्स में पुरोहित और मंत्रोच्चार तक "फास्ट फॉरवर्ड" कर दिए जाते हैं। यह बदलाव कहीं न कहीं विवाह को केवल मनोरंजन का साधन बना रहा है।

साथियों बात अगर हम समाज को दिशा दिखाने कीआवश्यकता व सादगीपूर्ण विवाह की करें तो, आज समय की मांग है कि समाज इस बदलते परिदृश्य पर गंभीर चिंतन करे। विवाह को पुनः उसके मूल स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। इसके लिए(अ) धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को विवाह संस्कारों की पवित्रता का प्रचार करना चाहिए। (ब) परिवारों को बच्चों को बचपन से ही विवाह संस्कारों की महत्ता सिखानी चाहिए।(क़) सरकार को दहेज और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने वाले कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। (ड) समाज में "सादगीपूर्ण विवाह" को प्रोत्साहित करने वाले अभियान चलाने चाहिए।सादगीपूर्ण विवाह--भविष्य की राहआज कई राज्यों में "सामूहिक विवाह" और "सादगीपूर्ण विवाह" की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें खर्च सीमित रखा जाता है और धार्मिक अनुष्ठानों को महत्व दिया जाता है। इससे न केवल आर्थिक बोझ कम होता है, बल्कि विवाह की सामाजिक और आध्यात्मिक महत्ता भी बनी रहती है।सादगीपूर्ण विवाह को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाना होगा। जब तक दिखावे और भव्यता को "प्रेस्टीज" माना जाएगा, तब तक यह प्रवृत्ति नहीं रुकेगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विवाह भारतीय संस्कृति का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे आधुनिकता और दिखावे की भेंट चढ़ाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। समाज को यह समझना होगा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों का पवित्र मिलन है, जिसका उद्देश्य धर्म, परंपरा और संस्कारों को आगे बढ़ाना है।यदि हम विवाह को पुनः उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप में स्थापित कर पाते हैं, तभी हम आधुनिकता के दंश से बचकर आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त और संस्कारित समाज दे पाएंगे।

हुंडई Ioniq 2 नई इलेक्ट्रिक कार की पहली झलक, जानें फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स

हुंडई IAA मोबिलिटी शो 2025 में अपने नए मोबिलिटी सॉल्यूशंस का प्रदर्शन करेगी। कंपनी ने एक नई कॉन्सेप्ट कार की झलक दिखाई है जो Ioniq 2 के नाम से आ सकती है। इसमें चिकनी बॉडी पैनलिंग और खास डिजाइन है। यह E-GMP आर्किटेक्चर पर आधारित होगी और 430 किमी की रेंज दे सकती है। इसका मुकाबला निसान माइक्रा और रेनॉल्ट 5 जैसी कारों से होगा।

नई दिल्ली। जर्मनी के म्यूनिख में होने वाले IAA मोबिलिटी शो 2025 में Hyundai अपनी अगली जनरेशन के मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लिए अपने रोडमैप को पेश करेगी। इस शो से पहले, Hyundai ने अपनी एक नई कॉन्सेप्ट कार की पहली झलक जारी की है। यह छोटी EV संभवतः Ioniq 2 नाम से प्रोडक्शन में आ सकती है। वहीं, यह अब तक की सबसे छोटी Ioniq भी कही जा रही है।

डिजाइन और बाहरी बनावट

Hyundai की तरफ से जारी की गई फोटोज में कॉन्सेप्ट कार में चिकनी और घुमावदार बॉडी पैनलिंग देखने के लिए मिली है। इसमें मेश-पैटर्न बम्पर इंटेक, स्पेशल खांचों के साथ ढलान वाला बोनट डिजाइन और फ्लेयर्ड व्हील आर्च भी दिया गया है। इसमें डकटेल स्पॉइलर और पीछे के बम्पर पर भी मेश-पैटर्न डिजाइन भी दिया गया है। इन तस्वीरों में लाइटिंग एलिमेंट्स स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन पहले देखी गई टेस्टिंग मॉडल में स्लीक LED हेडलैंप और DRLs देखने के लिए मिले थे। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट में आगे और पीछे दोनों तरफ पूरी चौड़ाई वाली एलईडी बार होंगी, जैसा कि फेसलिफ्टेड Hyundai Ioniq 6 सेडान में देखा गया था।

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज

उम्मीद है कि Hyundai की यह नई EV E-GMP आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेगी, जैसा Kia EV2 और EV3 क्रॉसओवर एसयूवी में देखा गया है। ऐसे में, यह 150 kW या 204 PS की पावर जेनरेट करने वाली सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर से लैस हो सकती है। इसे 58.3 kWh की बैटरी पैक से बिजली मिल सकती है, जिससे लगभग 430 किमी की WLTP रेंज मिलने की उम्मीद है।

Hyundai Ioniq 2 का मुकाबला निसान माइक्रा, रेनॉल्ट 5 E-Tech, सिट्रोएन e-C3, ओपल कोर्सा इलेक्ट्रिक, प्यूजो E-208 और BYD डॉल्फिन जैसी इलेक्ट्रिक कारों से देखने के लिए मिलेगा। Hyundai Ioniq 2 को 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में भी Ioniq 2 की संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

बाइक का इंजन ऑयल कब बदलें? अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है भारी नुकसान, जानें पूरी डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

बाइक इंजन ऑयल भारत में बड़ी संख्या में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। बाइक का इंजन सही तरह से काम करता रहे इसके लिए इंजन ऑयल काफी जरूरी होता है। अगर इंजन ऑयल खराब या कम हो जाए तो गंभीर नुकसान भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कब इंजन ऑयल को बदलना चाहिए। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में लोग रोज के कामों को पूरा करने के लिए बाइक का उपयोग करते हैं। कई लोग बाइक का अच्छी तरह ध्यान रखते हैं तो कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही बरतने पर इंजन को भी नुकसान होता है। कई बार लोग इंजन ऑयल को बिना बदले और चेक किए भी चलाते हैं। लेकिन ऐसा करना कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इंजन ऑयल को कब बदलना (bike engine oil change) बेहतर रहता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

लापरवाही से नुकसान

किसी भी बाइक में इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इंजन के लिए सबसे जरूरी इंजन ऑयल होता है। कई बार लोग इंजन और इंजन ऑयल को लेकर लापरवाही बरतते हैं। जिससे बाद में उनको भारी नुकसान हो जाता है।

मैनुअल बुक पढ़ना जरूरी

निर्माता की ओर से अपनी हर बाइक के साथ मैनुअल बुक या ई-मैनुअल बुक दी जाती है। बाइक की मैनुअल में हर बात की जानकारी के साथ ही यह भी जानकारी होती है कि किस बाइक में किस तरह के इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। साथ में यह भी जानकारी दी जाती है कि इंजन ऑयल को कब बदलना चाहिए। इसे पढ़कर आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि इंजन ऑयल को कब बदलना सही होगा।

इंजन से आवाज

अगर आपकी बाइक को चलाते हुए इंजन से सामान्य से ज्यादा आवाज आने लगती है, तो ऐसी स्थिति में इंजन ऑयल को बदलना काफी जरूरी हो जाता है। जब भी बाइक में नया इंजन ऑयल डाला जाता है तो इंजन की आवाज काफी कम हो जाती है, लेकिन जब भी ऑयल खराब हो जाता है तो इंजन से आने वाली आवाज बढ़ने लगती है।

ओवरहीट होने पर भी चेक करें

अगर आपकी बाइक चलते हुए काफी तेजी से ओवरहीट होने लगती है, तो भी इस बात की संभावना होती है कि इंजन ऑयल खराब हो गया हो। इसके साथ ही यह भी खतरा होता है कि इंजन में ऑयल का स्तर काफी कम हो गया हो। ऐसा होने पर इंजन को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर इंजन ऑयल को चेक कर उसे बदल देना चाहिए।

इस हफ्ते लॉन्च होगी हीरो मोटोकॉर्प की नई बाइक, 125 सीसी सेगमेंट में मुकाबला होगा कड़ा

हीरो की नई बाइक हीरो मोटोकॉर्प की ओर से देश में कई सेगमेंट में बाइक स की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते नई 125 सीसी बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से किस तरह के फीचर्स और इंजन के साथ नई बाइक को लॉन्च किया जाएगा। इसे किस कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई तरह की बाइक्स की बिक्री की जाती है। प्रमुख वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प भी कई सेगमेंट में अपनी बाइक्स की बिक्री करती है। निर्माता की ओर से इस हफ्ते में एक और नई बाइक को बाजार में लॉन्च (Hero New Bike) करने की तैयारी की जा रही है। इसे किस कीमत, फीचर्स और सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हीरो लॉन्च करेगी नई बाइक

हीरो मोटोकॉर्प की ओर से भारतीय बाजार में एक और नई बाइक को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से 125 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा।

टेस्टिंग के दौरान देखी गई थी बाइक

हीरो की नई बाइक को लॉन्च से पहले टेस्ट किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। जिसमें कई फीचर्स की जानकारी मिली थी।

कैसे होंगे फीचर्स

निर्माता की ओर से अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर के साथ देखा गया था। जिससे यह पता चलता है कि हीरो की नई बाइक में कारों वाले इस क्रूज कंट्रोल फीचर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एलईडी हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

कितना दमदार इंजन

नई बाइक में हीरो का 125 सीसी का मौजूदा इंजन दिया जा सकता है। इसमें 124.7 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन का उपयोग किया जा सकता है। जिससे इस बाइक को 10 हॉर्स पावर और 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। इस इंजन के साथ निर्माता की ओर से पांच स्पीड गियरबॉक्स को दिए जाने की उम्मीद है।

कब होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हीरो की नई बाइक को भारत में 19 और 20 अगस्त तक लॉन्च किया जा सकता है। इसे ग्लैमर नाम से ही लाया जा सकता है।

किनसे होगा मुकाबला

हीरो की नई बाइक को बाजार में 125 सीसी सेगमेंट में ऑफर किया जाएगा। इस बाइक का बाजार में सीधा मुकाबला होंडा शाइन 125, एसपी 125, बजाज पल्सर 125, टीवीएस जैसी बाइक्स

टोल प्लाजा पर नहीं लगेगा जाम, जल्द खुलेगा देश का पहला बिना बैरिकेटिंग वाला टोल

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। पहला MLFF टोलिंग सिस्टम गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा पर लागू होगा। वित्त वर्ष 2026 तक 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू करने की योजना है।

नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने देश में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और ICICI बैंक के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के तहत भारत का पहला मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम गुजरात के चोरयासी टोल प्लाजा (NH 48) पर लागू किया जाएगा।

कहां लागू होगा पहला MLFF टोल सिस्टम?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, इस करार पर हस्ताक्षर NHAI मुख्यालय (नई दिल्ली) में NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव और ICICI बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किए गए। चोरयासी टोल प्लाजा (गुजरात) देश का पहला ऐसा टोल प्लाजा होगा जहां बिना रुके टोल वसूला जाएगा। इसके साथ ही, हरियाणा के घरौंडा टोल प्लाजा (NH 44) पर भी इस सिस्टम को लागू करने की योजना है।

आने वाले समय में और भी प्लाजा होंगे शामिल

NHAI ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2026 (FY26) के दौरान करीब 25 राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर यह सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त टोल प्लाजाओं की पहचान की जा रही है। NHAI चेयरमैन संतोष कुमार यादव के अनुसार, यह समझौता देश में टोलिंग के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाएगा, बल्कि यात्रियों के लिए टोल अनुभव को भी आसान और सुविधाजनक बनाएगा।

MLFF क्या है और कैसे करेगा काम?

मल्टी-लेन फ्री-फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम एक ऐसा अत्याधुनिक समाधान है, जिसमें वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें RFID रीडर्स और ANPR कैमरों (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) के जरिए FASTag और वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) को स्कैन किया जाएगा। इसके जरिए टोल शुल्क स्वतः ही कट जाएगा और वाहन बिना रुके सीधे गुजर सकेगा। इस सिस्टम से जाम की समस्या कम होगी, समय बचेगा, ईंधन की खपत घटेगी और प्रदूषण भी कम होगा। सरकार का मानना है कि यह प्रणाली न केवल यात्रियों को राहत देगी बल्कि टोल वसूली को भी और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगी।

गाड़ी का स्टेयरिंग वाइब्रेट हो रहा है तो हो जाएं सावधान, ये हैं 4 बड़े कारण, जिनकी वजह से हो सकता है भारी नुकसान

कार स्टीयरिंग कंपन भारत में बड़ी संख्या में लोग कार का उपयोग करते हैं। लेकिन काफी कम लोगों को ही सही तरह से कार चलाना आता है। अगर आप भी लापरवाही से कार चलाते हैं तो कई बार कार के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या आ जाती है। कार में यह समस्या किन कारणों से होती है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार का उपयोग करते हैं। कई बार छोटी लापरवाही के कारण भी कार में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। ऐसी ही एक परेशानी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की होती है। यह परेशानी किस तरह की लापरवाही के कारण होती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सस्पेंशन में खराबी आना

जब कार को लंबे समय तक खराब सड़कों पर चलाया जाता है। तो कार के सस्पेंशन में खराबी आने का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक बार सस्पेंशन में खराबी आ जाती है तो फिर गाड़ी चलाने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या होने लगती है। अगर इस समस्या को समय रहते दूर न करवाया जाए तो फिर गाड़ी में और भी कई तरह की परेशानियों के आने का खतरा बढ़ जाता है। जिसे ठीक करवाने में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं।

ब्रेक रोटर में खराबी

गाड़ी को चलाने का सही तरीका काफी कम लोगों को पता होता है। ज्यादातर लोग जब कार में ब्रेक लगाते हैं तो वो काफी तेज ब्रेक लगाते हैं। जिससे कार के ब्रेक रोटर में खराबी आ जाती है। जब ब्रेक रोटर खराब हो जाए तो भी कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने लगता है। ब्रेक रोटर और ब्रेक पैड मिलकर ही कार को रोकते या स्पीड को कम करते हैं। लेकिन इनके खराब होने पर स्टेयरिंग में वाइब्रेशन हो जाता है।

अलाइनमेंट आऊट होना

गाड़ी के स्टेयरिंग में वाइब्रेशन को दूर रखने के लिए अलाइनमेंट का सही होना भी जरूरी होता है। गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट जब आऊट हो जाए तो कार चलाते हुए स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने की समस्या आ जाती है। ऐसा होने पर कार एक दिशा में जाने लगती है। साथ ही वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। इससे बचने के लिए समय समय पर कार के अलाइनमेंट को चेक करवाना चाहिए। ऐसा करने से स्टेयरिंग में वाइब्रेशन की समस्या को दूर रखा जा सकता है।

लापरवाही बरतने पर

अगर कार चलाते हुए लापरवाही बरती जाए और लंबे समय तक गाड़ी को खराब सड़कों, खराब ड्राइविंग पैटर्न के साथ चलाया जाता है तो भी स्टेयरिंग में वाइब्रेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही कई बार ऐसा मौसम में काफी ज्यादा बदलाव के कारण भी होने लगता है।

क्या अब स्टेट हाईवे के लिए अलग से फास्टैग लेना पड़ेगा? वहां टोल शुल्क कैसे कटेगा?

क्या सालाना फास्टैग पास लेने के बाद स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग से फास्टैग लेना जरूरी होगा? जानिए स्टेट हाईवे पर टोल कैसे कटेगा?

15 अगस्त से पूरे देश में FASTag Annual Pass (फास्टैग वार्षिक पास) शुरू हो गया है। यानी अब अगर कोई गाड़ी इस पास के जरिए हाईवे से गुजरेगी तो उसे 1 साल में 200 ट्रिप तक अलग से टोल नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए एकमुश्त 3000 रुपये पहले से भरने होंगे।

कहां-कहां मान्य होगा वार्षिक पास

15 अगस्त से शुरू हुआ यह फास्टैग वार्षिक पास सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई) द्वारा संचालित हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों पर ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि यह पास किसी भी स्टेट हाईवे, राज्य सरकार की सड़कों या प्राइवेट टोल रोड्स पर लागू नहीं होगा।

स्टेट हाईवे पर अलग पास की जरूरत है या नहीं?

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या अब स्टेट हाईवे पर यात्रा करने के लिए अलग पास बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक पास वहां काम नहीं करेगा। तो इसका जवाब है - नहीं। इसके लिए अलग से कोई पास लेने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, वार्षिक पास सीधे आपके गाड़ी में लगे फास्टैग से जुड़ा रहेगा। यानी अगर आप एनएचएआई के हाईवे पर चलेंगे तो वहां वार्षिक पास लागू होगा और टोल नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही आप स्टेट हाईवे पर आएंगे, वहां का टोल आपके सामान्य फास्टैग बैलेंस से कटेगा।

कैसे कटेगा टोल स्टेट हाईवे पर

अगर आप एनएचएआई के हाईवे पर सफर करते हुए बीच में स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो वहां का टोल अपने-आप आपके फास्टैग से कट जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आपके फास्टैग वॉलेट में हमेशा पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।

किसके अधीन होते हैं स्टेट हाईवे

स्टेट हाईवे पर टोल वसूली का सिस्टम राज्य सरकार या निजी ऑपरेटरों के हाथ में होता है। यह एनएचएआई या सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। इसी वजह से वार्षिक पास वहां लागू नहीं होता।

फास्टैग रिचार्ज रखें

यानि साफ है कि वार्षिक फास्टैग पास सिर्फ एनएचएआई के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य है। स्टेट हाईवे पर इसके लिए कोई अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। वहां भुगतान सामान्य फास्टैग से होगा, बस ध्यान रखें कि उसमें बैलेंस होना चाहिए।

सेल्फ लर्निंग फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन है

विजय गर्ग

विषय ज्ञान से परे, आत्म-शिक्षण जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कौशल का सम्मान करता है, जैसे महत्वपूर्ण सोच, समस्या-समाधान, समय प्रबंधन और आत्म-अनुशासन। प्रबंधन और कार्यस्थल में प्रबंधकों और पेशेवरों के लिए, स्व-सीखने की क्षमता अब एक लक्जरी नहीं है - यह एक आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और उद्योगों के विकास का मतलब है कि आपने कल जो सीखा वह कल प्रासंगिक नहीं हो सकता है। स्व-शिक्षण प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने का एक तरीका प्रदान करता है।

स्व-शिक्षण, या स्व-निर्देशित शिक्षा, तेजी से प्रबंधन और शिक्षा का भविष्य बन रहा है। यह व्यक्तियों को अपनी स्वयं की सीखने की यात्रा का प्रभार लेने का अधिकार देता है, जो एक ऐसी दुनिया में महत्वपूर्ण है जो लगातार बदल रही है। यह बदलाव सूचना की पहुंच, निरंतर कौशल विकास की आवश्यकता और आधुनिक कार्यस्थल की बदलती मांगों सहित कारकों के अभिसरण के कारण हो रहा है। सेल्फ लर्निंग के लाभ शिक्षा में स्व-शिक्षण छात्रों को यह तय करने की स्वायत्तता देता है कि वे क्या, कब और कैसे सीखते हैं। इस व्यक्तिगत दृष्टिकोण के कई फायदे हैं:

निजीकृत गति और शैली: छात्र एक गति से आगे बढ़ सकते हैं जो उन्हें सूट करता है, कठिन विषयों पर अधिक समय बिताता है और उन लोगों पर कम करता है जिन्हें वे पहले से जानते हैं। यह व्यक्तिगत सीखने की शैलियों और वरीयताओं को पूरा करता है, जिससे प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है।

गहरा जुड़ाव: जब कोई छात्र बाहरी दबाव के बजाय व्यक्तिगत जिज्ञासा से प्रेरित होता है, तो वे सामग्री के साथ अधिक व्यस्त हो जाते हैं। इससे बेहतर अवधारण और विषय की गहरी समझ होती है।

आवश्यक कौशल का विकास: विषय ज्ञान से परे, आत्म-शिक्षण जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कौशल का सम्मान करता है, जैसे महत्वपूर्ण सोच, समस्या-समाधान, समय प्रबंधन और आत्म-अनुशासन। प्रबंधन और कार्यस्थल में प्रबंधकों और पेशेवरों के लिए, स्व-सीखने की क्षमता अब एक लक्जरी नहीं है - यह एक आवश्यकता है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और उद्योगों के विकास का मतलब है कि आपने कल

जो सीखा वह कल प्रासंगिक नहीं हो सकता है। स्व-शिक्षण प्रतिस्पर्धी और प्रासंगिक बने रहने का एक तरीका प्रदान करता है।

सतत अपस्किलिंग और रिस्किलिंग: जीवन भर चलने वाली एकल डिग्री का पारंपरिक मॉडल अप्रचलित है। सेल्फ लर्निंग कर्मचारियों को लगातार अपस्किल और रिस्किल करने, नए ज्ञान प्राप्त करने और आवश्यकतानुसार एआई और बड़े डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों के अनुकूल होने की अनुमति देता है।

अनुकूलन क्षमता में वृद्धि: स्व-निर्देशित सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठनों में अधिक अनुकूलनीय और लचीला कर्मचारी होते हैं। ये व्यक्ति जटिल चुनौतियों को नेविगेट करने और परिवर्तन को गले लगाने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हैं, जिससे पूरा संगठन अधिक चुस्त हो जाता है।

कर्मचारी सशक्तिकरण और प्रेरणा: जब कंपनियां कर्मचारियों को अपने पेशेवर विकास पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती हैं, तो यह उनके आत्मविश्वास, प्रेरणा और जुड़ाव को बढ़ाता है। स्वामित्व की यह भावना अधिक सक्रिय और प्रतिबद्ध कार्यबल की ओर ले जाती है। प्रौद्योगिकी की भूमिका स्व-अधिगम का उदय तकनीकी नवाचार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना दिया है, जिससे कहीं से भी लगभग कुछ भी सीखना संभव हो जाता है।

विशाल संसाधन: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पाठ्यक्रम और शैक्षिक ऐप पारंपरिक शिक्षा की तुलना में कम लागत पर अक्सर ज्ञान का एक विशाल पुस्तकालय प्रदान करते हैं। कौरसेरा, एडएक्स और खान अकादमी जैसे प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों से सामग्री तक पहुंच प्रदान करते हैं।

एआई और एनालिटिक्स: एआई का उपयोग व्यक्तिगत सीखने के रास्ते बनाने, वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करने और किसी व्यक्ति की प्रगति और जरूरतों के आधार पर संसाधनों की सिफारिश करने के लिए किया जा रहा है। यह आत्म-शिक्षण अनुभव को अधिक निर्देशित और प्रभावी बनाता है।

आभासी और संवर्धित वास्तविकता: वीआर और एआर जैसी तकनीकों का उपयोग इमर्सिव, अनुभवात्मक सीखने के वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा है, विशेष रूप से जटिल या हाथों पर कौशल के लिए, सर्जिकल प्रशिक्षण से लेकर प्रबंधन सिमुलेशन तक। चुनौतियां और मानव तत्व जबकि आत्म-शिक्षा शक्तिशाली है, यह इसकी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसके लिए उच्च स्तर की आत्म-प्रेरणा और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हर कोई स्वाभाविक रूप से एक स्व-स्टार्टर नहीं है, और एक संरचित पाठ्यक्रम या पारंपरिक समर्थन प्रणाली की कमी एक बाधा हो सकती है। यह वह जगह है जहां मानव तत्व महत्वपूर्ण रहता है। भविष्य में, शिक्षकों और प्रबंधकों की भूमिका केवल सूचना देने वालों से लेकर सूत्रधार और आकाओं तक पहुंच जाएगी। वे अपनी आत्म-सीखने की यात्रा में व्यक्तियों का मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें लक्ष्य निर्धारित करने, विश्वसनीय संसाधन खोजने, प्रेरित रहने और वास्तविक दुनिया की स्थितियों में अपने नए ज्ञान को लागू करने में मदद करेंगे। शिक्षा और प्रबंधन का भविष्य शिक्षकों या प्रबंधकों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि अधिक स्वतंत्र और निरंतर सीखने वाले मॉडल का समर्थन करने के लिए अपनी भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने के बारे में है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

विज्ञानियों ने 2,500 साल पुरानी खोपड़ियों के बनाए चेहरे

विजय गर्ग

तमिलनाडु के मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने 2,500 साल पुरानी खोपड़ियों के चेहरे का डिजिटल पुनर्निर्माण किया है। उनका कहना है कि ये खोपड़ियां दो पुरुषों की हैं जो खोदाई के दौरान पुरातात्विक स्थल कीलाड़ी से लगभग चार किलोमीटर दूर कोंडगाई से निकाली गई थीं। उन खोपड़ियों में से एक दांत का उपयोग डिजिटल रूप से चेहरा बनाने के लिए किया गया है ताकि यह समझा जा सके कि इस क्षेत्र के लोग कैसे दिखते थे।

कीलाडी एक पुरातात्विक स्थल है, जो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित है। यहाँ संगम युग की शहरी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल से मिले साक्ष्यों, जैसे पक्की ईंटों से बने मकान, नालियां, मिट्टी के बर्तन और ब्राह्मी लिपि से पता चलता है कि लगभग 7,500 साल पहले यहां एक उन्नत और परिष्कृत शहरी जीवन मौजूद था। यह स्थान न केवल इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति की क्षेत्रीय प्रकृति को भी दर्शाता है।

तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग के अनुसार, कीलाडी में 580 ईसा पूर्व की एक शहरी सभ्यता का अस्तित्व था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ती है। यह खोज यह दर्शाती कि दक्षिण भारत में भी एक स्वतंत्र प्राचीन सभ्यता थी। कीलाही के लोग शिक्षित, कुशल और व्यापार में संलग्न थे। वे ईंट के घरों में रहते थे और लोगों की मृत्यु होने पर उन्हें बड़े बर्तनों में दफनाते थे। अब तक इस स्थल से लगभग 50 ऐसे बर्तन निकाले जा चुके हैं।

बीबीसी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ता अब इन बर्तनों में मिलीं खोपड़ियों, हड्डियों और अन्य वस्तुओं से डीएनए निकालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कीलाडी के निवासियों की जीवनशैली को समझा जा सके। विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जी. कुमारेसन का कहना है, 'हम अपने पूर्वजों की उत्पत्ति और प्रवास के तरीके को समझना चाहते हैं।' खोपड़ियों के चेहरे का पुनर्निर्माण श्रीडी स्कैन से शुरू हुआ, जिसे लिवरपूल जान मूर विश्वविद्यालय के फेस लैब में भेजा गया। वहां विशेषज्ञों ने कंप्यूटर साफ्टवेयर का उपयोग करके मांसपेशियों, मांस और त्वचा को जोड़ा। हालांकि, रंग जोड़ना एक बड़ी चुनौती थी। प्रोफेसर कुमारेसन ने बताया कि रंगों का चयन वर्तमान तमिलनाडु के लोगों की शारीरिक विशेषताओं के अनुसार किया गया।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

बदलता परिवेश

विजय गर्ग

हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें एक आम लड़की के सामने प्रश्न आता है- आप अपने लिए क्या खोज रही हैं। बिना एक पल गंवाए उत्तर आता है- सच्चा प्यार... अदरक वाली चाय... एक ऐसा साथी, जो बीच सफर में छोड़ के न जाए। इसे देखा-समझा और महसूस भी किया जा सकता है कि यह चाह और विश्वास है एक लड़की का... स्वयं के होने का । यह भाव नया नहीं है । यह तो सदियों से हर लड़की के मन में उस समय से रहता है, जब उसकी आंखों में नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं और तब तक नहीं मरता, जब तक उसकी सांस टूट नहीं जाती । यह भाव एक लड़की का महिला बनने तक के सफर का विश्वास होता है, जो उसे सोच देता है, समझ देता है। जीने की लालसा देता है और अपने पड़ाव को सुदृढ़ बनाने की क्षमता तथा हौसला देता है।

हम याद कर सकते हैं अपनी उस पीढ़ी को जो हमारी दादी और नानी की थी। फिर हमारी मां की थी और अब हमारी और हमारे बच्चों की। इन चार पीढ़ियों ने ही जीवन के फैसले लेने के न जाने कितने आधार बनाए । दादी-नानी ने अपनी उम्र बीतने के बाद अपने फैसले लेने शुरू किए तो मां ने हम बच्चों के बड़े होने पर। इस नई पीढ़ी के पहले वाले माता-पिता ने दोनों के बीच का रास्ता चुना, पर आज के बच्चे स्वयं अपना निर्णय ले रहे । शायद इसीलिए वे एक नया इतिहास बनाते हुए खुद को देख रहे हैं, जिसे समय समझा रहा है कि देखो, एक नई लहर आ रही है... एक नए युग का संकेत प्रारंभ हो चुका है।

कई वैसी कहानियां आज की लड़कियां गढ़ रही हैं, जिसकी कल्पना कभी हमारी दादी-नानी ने की भी नहीं होगी। अगर कभी की भी होगी, तो हासिल शायद ही कुछ हुआ हो। मगर पहले का वह हारा हुआ हौसला, जो पितृसत्तात्मक सोच, पुरानी पीढ़ी के बंधन में घुट रहा था, आज बेबाकी से उस सोच, बंधन को पीछे छोड़ती-काटती आज की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। उच्च शिक्षित या ऊंचे पद काम करती लड़कियों ने अपनी मेहनत और बुद्धि से यह सिद्ध कर दिया है कि समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का रास्ता रोके, हम आगे बढ़ेंगे। समय के हर पुराने अनुबंध को तोड़ कर । मगर समय की उन्नति का प्रवाह तब और सामर्थ्यवान बन जाता है, जब लड़कियां तिपहिया और कैब में सवारियों को बैठा कर उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं। कुछ लोग इसे मजबूरी मानेंगे, पर यह मानसिक शक्ति और धैर्य का रूपक है। समाज से लड़ने का साहस है। आज रास्ते हैं तो चुनौतियां और परेशानियां भी हैं। ऊंचाई पर बैठी लड़कियों को या तो पीछे धक्का देने का दुस्साहस किया जाता है या 'लड़की होने का फायदा' जैसी टिप्पणियां की जाती हैं। तिस पर तिपहिया या कैब चालक लड़कियों को समूह से अलग करने का दुस्साहस । चुनौतियां उनके दोनों ओर हैं । उनके साहस और सफलता पर फांस-सी अंगुलियां दोनों ओर हैं, पर अब लड़कियों का विश्वास पीढ़ियां पार करता उनकी हथेली में भर चुका है। वे चल पड़ी हैं अपने-अपने रास्ते उस कलाकार की तरह जो एक रस्सी पर अपने पैर को विश्वास से जमाए जमीन में गड़ी बल्ली के इस पार से उस पार चली जाती है । यह साहस और विश्वास किसी लड़की के लिए उसके परिवार का होता है, वह चाहे किसी भी श्रेणी का हो।

समाज की जड़ता या संकीर्णता वहां हारती है, जहां परिवार लड़कियों की हर सफलता-असफलता, जीत-हार में एक स्तंभ की तरह साथ खड़ा होता है, क्योंकि नकारात्मकता और अतिशयोक्ति हर जगह होती है, पर विश्वास हर जगह अपनी जमीन बना लेता है। बाईस वर्ष की एक लड़की ने 'मिग 21 बाइसन' लड़ाकू विमान को अपनी क्षमता और विश्वास के साथ उड़ा कर यह दिखा दिया कि क्षमताएं किसी की बंधक नहीं हैं। समझा दिया कि हमारे भीतर भी दक्षता और आत्मबल है । दूसरी ओर, पिछले दो दशकों से दिल्ली में तिपहिया या आटोरिक्शा चलाने वाली एक महिला को पहले लोगों ने कहा था कि लड़कियों का आटो चलाना सम्मान की बात नहीं होती... यह काम पुरुषों का है। मगर इस महिला को उस समय यही एक रास्ता दिख रहा था अपना परिवार चलाने के लिए, इसलिए उसने किसी की नहीं सुनी। बहुत दिनों तक लोगों ने परेशान भी किया, बदतमीजी की, पर कुछ लोग बहुत अच्छे भी मिले, जिन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया तथा सहायता भी की। यही थोड़े- से अच्छे लोग शक्ति बन गए और वह पूरी तरह आटो ड्राइवर बन गई। लड़ती भिड़ती, अपनी जगह बनाती ।

इस तरह हम देखते हैं कि यह परिवर्तन एक दिन, एक दशक का

नहीं है, न ही किसी आंदोलन के नारों से जन्मा है और न किसी सरकारी सूत्र का आग्रह है । यह परिवर्तन समय के साथ बदलते पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का है। टूटती पुरानी रूढ़ियों का है, जिसे शिक्षा, आधुनिक परिवेश और प्रौद्योगिकीकरण ने निर्मित किया ।

समस्याएं खत्म हो गईं हों, ऐसा नहीं है। न ही आज तक पुरुष-महिला के बीच समानता का कोई निश्चित मापदंड बन सका है। फिर भी पहले की तरह न अब कड़े प्रतिबंध हैं, न ही कोई बाधा, लेकिन कई नई चुनौतियां नए रूप में आज भी खड़ी हैं। यह साफ है कि इन सबके बीच आज लड़कियों को जीना आ गया है। अपना रास्ता, अपने लिए जगह बनाना आ गया है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

बदली खानपान की आदतों से बढ़ी मुसीबत

विजय गर्ग

देश में जिस तेजी से मोटापा और उससे जनित रोगों का दायरा बढ़ा है, उससे यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात जैसी स्थिति बनती जा रही है। जिससे मोटापा जनित गैर संक्रामक रोगों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक हालिया अध्ययन में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है कि साल 2025 तक भारत की वयस्क आबादी में मोटापे की दर 20 से 23 फीसदी तक जा पहुंची है। जबकि वर्ष 1990 में देश यह दर महज नौ से दस प्रतिशत ही थी। चिंता की बात यह है कि महज तीन दशक में मोटापा बढ़ने की यह दर दो गुना हो चुकी है। यही वजह है कि शहरों में आजकल हर चौथा व्यक्ति मोटापे का शिकार दिखायी देता है। दरअसल, देश में जैसे-जैसे आर्थिक समृद्धि आई तो हमारी खान-पान की आदतों में बदलाव आया है। हमारे भोजन में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अधिक शूगर वाले पेय पदार्थ और युवाओं में जंक फूड का उपभोग तेजी से बढ़ा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि खाद्य तेलों का उपयोग भी बहुत तेज गति से बढ़ा है। आर्थिक विकास से समृद्धि आई तो हमारा खानपान समृद्ध हुआ,लेकिन वहीं शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ी है। दरअसल, खाद्य तेलों का बेतहाशा उपयोग भी मोटापे की वजह बना है। देश में नब्बे के दशक में जहां प्रति व्यक्ति तेल की औसतन खपत साढ़े तीन से चार लीटर थी, जो अब करीब बीस लीटर सालाना हो गई है। यानी चिंताजनक स्थिति तक पहुंचकर पांच गुना हो गई है। अब मोटापे की समस्या से शहर ही नहीं, ग्रामीण जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीती सदी में ऐसा देखने में नहीं आता है। दरअसल, इस सदी की शुरुआत में आई आर्थिक समृद्धि ने न केवल हमारी खानपान की आदतें बदली, बल्कि वाहनों के अधिक उपयोग व आरामदायक जीवनशैली ने हमारी शारीरिक सक्रियता भी कम कर दी। जो मोटापे की एक बड़ी वजह बना।

देश में मोटापे की समस्या किस हद तक पहुंच चुकी है और उससे गैर संक्रामक रोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देश में गति पकड़ते मोटापे पर गंभीर चिंता जतायी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भी वे मोटापे से मुक्त जीवन के लिये लाइफ स्टाइल में बदलाव की बात कह चुके हैं। उन्होंने खाद्य तेलों के उपयोग में कमी लाने की भी बात कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि पांच-छह सौ एमएल से अधिक खाद्य तेल का सेवन मोटापे, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खानपान की आदतों में सुधार और शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से हम मोटापा कम कर सकते हैं। नियमित व्यायाम व योग-प्राणायाम इसमें खासे मददगार हैं। यहां संकट हमारी जीवन शैली में आये बदलावों का भी है, जिसमें हम देर रात को अधिक गरिष्ठ भोजन करते हैं। देर से सोना और देर से जागना अब आम बात हो चली है। तेजी से होते शहरीकरण, आफिसों में देर तक काम करने, शारीरिक सक्रियता में कमी तथा देर रात तक सोशल मीडिया में उलझे रहने से भी नींद की कमी ने जीवन में तनाव को बढ़ाया है। यह तनाव हमारी खानपान की आदतों को बुरी तरह प्रभावित करके मोटापे को बढ़ाता है। यही वजह है कि एक बहुचर्चित मेडिकल पत्रिका ने चेताया है कि भारत में 2050 तक पैंतालीस करोड़ युवा मोटापे की चपेट में आ सकते हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि सोशल मीडिया पर मोटापा कम करने के नीम-हकीमी नुस्खों की भरमार आई है। हर दूसरा आदमी मोटापा कम करने के तरीके बताता नजर आता है। जबकि चिकित्सीय दृष्टि ये तथ्य प्रमाणिक नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग आंख मूंदकर उस पर विश्वास करने लगते हैं। कुछ लोग जिम जाकर रातों-रात वजन घटाने का उपक्रम करके अपने शरीर से खिलवाड़ करने लगते हैं। वजन घटने में सावधानी की लंबी प्रक्रिया भी होती है। जल्दीबाजी के चक्कर में कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं।

शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी : सुविधा से जंजाल तक की यात्रा

हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी : सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

सरकार ने पारदर्शिता और न्याय की मंशा से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और असंतोष का कारण बन चुकी है।

हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जो 2016 में शिक्षकों के लिए पारदर्शिता का प्रतीक बनकर आई थी, अब उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्षों से ट्रांसफर लंबित हैं, ब्लॉक सिस्टम बाधा बन गया है और विद्यालयों में शिक्षकों का असंतुलन गहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव चलाए और पॉलिसी में सुधार करे, ताकि न तो शिक्षक परेशान हों और न ही छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो।

✍ डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। उस समय इसे शिक्षा जगत में बड़े सुधार के रूप में देखा गया। दशकों से यह आरोप लगता रहा कि तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहते थे। कई शिक्षक मनचाही जगह सेवा करते थे जबकि अन्य दूरदराज़ और कठिन क्षेत्रों में वर्षों तक फंसे रहते थे। इस असमानता ने शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुँचाया।

ऑनलाइन पॉलिसी ने शुरू में उम्मीद जगाई। कहा गया कि शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करेंगे और मेरिट के आधार पर तबादला होगा। इससे भेदभाव खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। परंतु नौ साल बाद यह योजना अब विवादों और असंतोष का दूसरा नाम बन चुकी है।

आश्वासन और हकीकत

हर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस साल भी अप्रैल में घोषणा की गई थी कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रांसफर सत्र शुरू होने से पहले कर दिए जाएंगे। मगर अगस्त बीत गया और शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। जब-जब ऐसी घोषणाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो शिक्षकों का मनोबल टूटता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।

ब्लॉक सिस्टम की पेचीदगी

इस नीति की सबसे बड़ी खामी "ब्लॉक सिस्टम" है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और शिक्षक नज़दीकी ब्लॉक में ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ। कई बार एक ही ब्लॉक में किसी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होती है, वहीं कुछ विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ मौजूद होता है। नीति की जटिलता के कारण समायोजन नहीं हो पाता और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

एक उदाहरण समझिए—मान लीजिए एक ब्लॉक में गणित के शिक्षक की 15 सीटें हैं लेकिन वहां 20 शिक्षक तैनात हैं, जबकि उसी जिले के दूसरे ब्लॉक में 10 सीटें खाली पड़ी हैं। ब्लॉक सिस्टम के कारण अतिरिक्त शिक्षक चाहकर भी खाली स्कूलों में नहीं भेजे जा सकते। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है।

शिक्षकों का दृष्टिकोण

शिक्षक केवल अपनी सुविधा के लिए तबादले नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी मेहनत सार्थक हो सके। जब वर्षों तक ट्रांसफर लंबित रहते हैं, तो शिक्षक घर-परिवार से दूर रहकर मानसिक तनाव झेलते हैं। कई महिला शिक्षक छोटे बच्चों को छोड़कर दूरदराज़ स्थानों पर सेवाएँ दे रही हैं। ऐसे हालात में उनका मन पढ़ाई पर कितना केंद्रित रह पाता होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं।

दूसरी ओर, कई शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए हैं। इससे उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यह भी सच है कि लंबे समय तक एक ही विद्यालय में रहने वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्थानीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और शिक्षा से ज्यादा निजी हितों में उलझ जाते हैं। इस असंतुलन को खत्म करना बेहद जरूरी है।

शिक्षा पर असर

जब किसी विद्यालय में वर्षों तक विज्ञान या गणित का शिक्षक नहीं होता, तो छात्र पीछे रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरते हैं और इसका दोष अक्सर छात्रों या अभिभावकों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार प्रणाली है, जो समय पर सही अध्यापक नहीं भेज पाती। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) कहता है कि हर विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी की कमजोरियों ने इस लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है।

संगठन की भूमिका

हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए। यदि कोई स्कूल खाली रह जाता है, तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डिप्यूटेशन का अधिकार दिया जाए। यह सुझाव व्यवहारिक है, क्योंकि इससे तत्कालीन संकट टाला जा सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी इच्छाशक्ति दिखाएगी? कई बार लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जब चाहा प्रक्रिया रोक दी जाती है और जब चाहा कुछ तबादले चुनिंदा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इससे शिक्षकों का विश्वास डगमगाता है।

डिजिटलाइजेशन बनाम ज़मीनी हकीकत

सरकार ने पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालकर इसे "ई-गवर्नेंस" की सफलता बताया। लेकिन केवल पोर्टल बना देने से समस्या हल नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उसमें समयबद्धता और जवाबदेही हो। यदि हर साल प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी महज़ दिखावा बनकर रह जाता है।

आज हाल यह है कि कई शिक्षक हर साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस जमा करते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, लेकिन अंत में परिणाम "कोई ट्रांसफर नहीं" निकलता है। ऐसे में उनमें गुस्सा और हताशा स्वाभाविक है।

शिक्षा मंत्री और हकीकत

शिक्षा मंत्री बार-बार कहते हैं कि "जल्द ही ट्रांसफर होंगे" लेकिन नौकरशाही और नीति की जटिलता के कारण बात आगे नहीं बढ़ती। इस बीच, सत्र बीत जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती।

समाधान क्या है?

1. ब्लॉक सिस्टम की समीक्षा – इसे या तो खत्म किया जाए या लचीला बनाया जाए, ताकि शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों तक पहुँच सकें।

2. समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव – हर साल अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया जाए।

3. डिप्यूटेशन का अधिकार जिला स्तर पर – खाली स्कूलों को भरने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाए।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही – यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पष्ट कारण बताए जाएं।

5. मानवीय दृष्टिकोण – महिला शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान हों।

शिक्षा की आत्मा

समाज में शिक्षा सबसे पवित्र कार्य है। यदि शिक्षक ही असंतोष में रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुँचाएंगे? एक निराश और हताश शिक्षक बच्चों को वही भाव देगा जो उसके भीतर है। इसलिए शिक्षक की समस्याओं को केवल "ट्रांसफर की मांग" मानकर टालना सही नहीं। यह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मज़बूत करने का सवाल है।

सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को केवल "डाटा" न माने, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला समझे। शिक्षक का मनोबल तभी ऊँचा होगा जब उसे न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।

सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक इस नीति में पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं जुड़ता, तब तक यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती फाइलें भर रहेगी, जमीनी हकीकत में नहीं।

शिक्षकों की आवाज़ अनसुनी करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर इस जंजाल को दूर करना चाहिए। तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाएंगे।

राहुल गांधी आदेश दें तो झारखंड में भाजपा के सभी कार्यालय तोड़ देंगे : डा० इरफान अंसारी

बिहार में कांग्रेस कार्यालय तोड़ें जाने पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का गर्म बयान

रांची, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का एक गर्म बयान सामने आया है, जिसका असर झारखंड राजनीति में दिख सकता है । बिहार में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री सह जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राहुल गांधी के आदेश का इंतजार है। अगर एक बार आदेश मिल गया तो भाजपा के जितने भी कार्यालय झारखंड में हैं, सभी को तोड़ देंगे। उनके इस बयान के बाद झारखंड का राजनीतिक तापमान एक बार फिर से गरम हो सकता है ।बिहार की इस घटना से झारखंड के कांग्रेसी आक्रोश में हैं। अंसारी ने ये बातें शनिवार को जामताड़ा कोर्ट रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी इस यात्रा से भाजपा में बौखलाहट आ गई है। उनके समर्थक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए हैं। भाजपा वालों ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के निजी जीवन पर कई बार अभद्र टिप्पणी की है। उस दरम्यान राहुल गांधी ने सभी को सब्र रखने को कहा था। लेकिन बिहार की घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सब्र को तोड़ने का काम किया है। इस बयान को लेकर भाजपा की तरफ से कड़ प्रतिक्रिया आने की संभावना है ।अंसारी ने कहा कि भाजपा में दम है तो ऐसी घटना झारखंड में करके दिखाए। हम बस राहुल गांधी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भाजपा का एक भी कार्यालय झारखंड में नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, जनता की बात सड़क पर लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं। किसी के घर में नहीं घुसने गए हैं। भाजपा बौखलाहट में जिस तरह से कदम उठा रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार में बदलाव तय है

झारखंड के प०सिंहभूम जिले में दो कुख्यात माओवादी हिडिमा तथा शिवा गिरफ्तार

हिडिमा छत्तीसगढ़ का शिबा सरायकेला जिले के कुचाई का । ओडिशा बांको खदान विस्फोटक लूट में शिवा संलिप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

चाईबासा, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से रविवार को जंगल से सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस, कोबरा-209 और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 31 अगस्त को दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें संगठन का सब जोनल कमेटी सदस्य संदीप उर्फ हिडिमा पाडेयाम (छत्तीसगढ़, बीजापुर जिला, गोरनाम निवासी) और एरिया कमेटी सदस्य शिवा बोदरा उर्फ शिबु (सरायकेला, कुचाई थाना क्षेत्र के जोजोडीह, जोमरो टोला निवासी) शामिल हैं।

दोनों नक्सली 40 से अधिक माओवादी वारदातों में वांछित थे। शिवा बोदरा की संलिप्तता ओडिशा के राउरकेला जिले के केबलांग थाना क्षेत्र स्थित बांको गांव में हुए विस्फोटक लूटकांड में भी पाई गई है।

गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षाबलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इसमें पिस्टल – 01, करतूस – 11, मैगजीन – 02 वॉकी-टॉकी – 02 डेटोनेटर – कई आइईडी बनाने से संबंधित सामग्री आदि मिले हैं

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना थी कि माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु, अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया और अश्विन सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर हमला करने और नई भर्ती करने के उद्देश्य से सक्रिय हैं।

इस पर एएसपी अभियान पारस राणा के नेतृत्व में विशेष अभियान दल गठित किया गया। झारखंड पुलिस और कोबरा 209 ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया और बड़ी सफलता हासिल की।

गिरफ्तार नक्सलियों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। इनके अनुसार संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल उर्फ रमेश महिला दस्ता सदस्यों का शारीरिक शोषण करता है और अवैध गर्भपात भी करवाता है। पुलिस इस खुलासे की गहराई से जांच कर रही है और माओवादी संगठन की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए है

झारखंड के पूर्व मंत्री एनस व पत्नी मेनन को सात साल, डीसीएलआर कार्तिक प्रभात को पांच साल की सजा

मामला सीएनटी एक्ट उलंघन कर जमीन खरीद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम (CNT- ACT) का उल्लंघन कर जमीन खरीदने के मामले में में झारखंड सरकार के एक पूर्व मंत्री एनस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को सीबीआई की विशेष अदालत ने 07-07 साल की सजा सुनायी है। इसके अलावा दोनों पर 01-01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 06 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रांची के तत्कालीन एवं आर डी सी एल आर कार्तिक कुमार प्रभात को 05 साल की सजा और 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने अन्य आरोपियों को धारा 193बी के तहत 02 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। मणिलाल महतो, ब्रजेश्वर महतो और अनिल कुमार फिरोज अख्तर को भी 05 साल की सजा और 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। अन्य आरोपियों को 04 साल की सजा और 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।

इस मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने सीएनटी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े आरोपों में 09 लोगों को दोषी ठहराया। आरोपों के अनुसार, मंत्री रहते हुए एनोस एक्का ने अपने पद का दुरुपयोग किया और फर्जी पते पर अवैध रूप से आदिवासी जमीन की खरीद-फरोख्त की। इसमें तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी कार्तिक कुमार प्रभात ने उनकी मदद की। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-फरोख्त की गयी।

बताते चलें कि एक आरोपी गोवर्धन बैठा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सीएनटी एक्ट के 15 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की गयी। हिनू में 22 कट्ठा जमीन, ओरमांझी में 12 एकड़, नेवरी में 04 एकड़, चुटिया के सिरम टोली मौजा में 09 डिसमिल जमीन एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के नाम पर खरीदी गयी। जमीन की सारी खरीदारी मार्च 2006 से मई 2008 के बीच की गयी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 04 अगस्त 2010 को एनोस एक्का व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने दिसम्बर 2012 में चार्जशीट दाखिल की। 05 नवम्बर 2019 को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में एनोस एक्का व अन्य के खिलाफ आरोप तय किये थे। 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आदेश के लिए आज की तारीख तय की। मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन एलआरडीसी सीकार्तिक कुमार प्रभात, राज किशोर सिंह, फिरोज अख्तर, ब्रजेश मिश्रा, अनिल कुमार, मणिलाल महतो, गोवर्धन बैठा, परशुराम केरकेट्टा और ब्रजेश्वर महतो ने मुकदमे का सामना किया।

भारत के सहकारिता आंदोलन पर घातक प्रहार होगा अमेरिका का 'ब्लड मील'

हरीश शिवनानी

किसी शक्तिशाली, साधन-सम्पन्न और प्रभुत्ववादी देश का अहंकारी, सनकी राष्ट्राध्यक्ष यदि अपनी निजी खुन्नस में अतार्किक, अव्यावहारिक और अनर्थकारी निर्णय दूसरे देशों पर थोपने पर आमादा हो जाए तो स्थिति गंभीर और सतर्क, सजग रहने जैसी हो जाती है। अमेरिका ने भारत के लिए यही स्थिति उत्पन्न कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत द्वारा उसे 'ऑपरेशन सिंदूर' सीज़फायर का (झूठा) श्रेय न देने और नोबल पुरस्कार की संस्तुति न करने और अमेरिकी डेयरी उत्पादों के लिए बाज़ार न खोलने से खिन्न होकर भारत पर अत्यधिक टैरिफ थोप दिए हैं। यह भारत में बरसों से बनाए गए सहकारिता आंदोलन और किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण समय है।

भारत का डेयरी उद्योग ग्रामीण विकास और किसानों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। सहकारी आंदोलन के माध्यम से विकसित यह उद्योग, विशेष रूप से अमूल, मदर डेयरी और अन्य कई ब्रांडों के जरिए, दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है; लेकिन पिछले कुछ समय में अमेरिका द्वारा अपने डेयरी उत्पाद भारत पर आयात करने के लिए दबाव डाल रहा है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में इसे 'ट्रेड बैरियर' बताते हुए सख़्त विरोध किया है और इसके आयात की मंजूरी देने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। एक मुख्य कारण यह है कि यदि अमेरिकी 'ब्लड मील' वाले डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोल दिए तो सस्ते अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार पर कब्जा कर लेंगे, जो भारतीय सहकारी उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे पर घातक प्रहार करेंगे।

अमेरिकी डेयरी उद्योग उत्पादकता बढ़ाने के लिए गायों को खिलाए जाने वाले चारे में 'ब्लड मील', 'बोन मील' और अन्य पशु उप-उत्पादों का इस्तेमाल करता है। 'ब्लड मील' पशु रक्त, मृत पशुओं की हड्डियों और मांस से बनाया जाता है, जो प्रोटीन का सस्ता स्रोत है और गायों के दूध उत्पादन को बढ़ाता है। इन उत्पादों में 'ब्लड मील' इस्तेमाल होने के कारण इन्हें मांसाहारी माना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और शाकाहारी परंपराओं के विपरीत है। यदि ये आयात बढ़े, तो भारत के सहकारी डेयरी उद्योग पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है, जिससे करोड़ों किसान और दुग्धपालक प्रभावित होंगे और जिसका सीधा असर भारत के सहकारिता आंदोलन पर पड़ेगा।

भारत में सहकारी डेयरी आंदोलन की शुरुआत 1946 में गुजरात के आनंद जिले से हुई, जब किसानों ने मिलकर कायरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (अमूल) की स्थापना की। अमूल मॉडल ने किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा, बिचौलियों को हटाया और उचित मूल्य सुनिश्चित किया। आगे चलकर 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम को तीन चरणों में व्यवस्थित रूप से नए सहकारी संघ जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 73,000 हो गई। ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया, जहां आज करीब आठ करोड़ किसान और पशुपालक जुड़े हैं।

यह आंदोलन न केवल आर्थिक रूप से सफल रहा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी बना। सहकारी मॉडल ने जाति और लिंग भेदभाव को कम किया, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज भारत का डेयरी सेक्टर जीडीपी में लगभग चार प्रतिशत योगदान देता है; अब अमेरिका इस आंदोलन को चुनौती दे रहा है। भारत में 'नॉन-वेज मिल्क' भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अस्वीकार्य है। 'ब्लड मील' न केवल सांस्कृतिक रूप से विवादास्पद है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इसमें बैक्टीरिया या रोगाणु हो सकते हैं, जो दूध के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। 'ब्लड मील' युक्त अमेरिकी डेयरी आयात के खतरे बहुआयामी हैं। सबसे प्रमुख है आर्थिक खतरा। अमेरिकी उत्पाद सब्सिडी प्राप्त होते हैं, इसलिए वे सस्ते हैं। इनके आयात से भारत में दूध की कीमतें 15 फीसदी तक गिर सकती हैं, जिससे भारतीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सालाना 1.03 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। अनेक सहकारी संघ, जो छोटे किसानों पर निर्भर हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। इससे लाखों सीमांत किसान विस्थापित हो सकते हैं।

दूसरा है सांस्कृतिक खतरा। भारत में लगभग 80 फीसदी आबादी शाकाहारी है और यहाँ दूध को पवित्र माना जाता है। 'ब्लड मील' युक्त दूध का आयात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। यह 'सांस्कृतिक ब्लासफेमी' जैसा होगा। भारत का सहकारी मॉडल स्थानीय और टिकाऊ है, जो छोटे फार्म्स पर आधारित है। आयात से यह संतुलन बिगड़ जाएगा और सहकारी आंदोलन पर प्रभाव गहरा होगा। ऑपरेशन फ्लड ने जो किसानों को संगठित किया, आयात से वह सहकारी संघ कमजोर हो जाएंगे। निजी कंपनियां बढ़ेंगी, जो किसानों का शोषण कर सकती हैं। ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी, और महिलाओं की भागीदारी कम होगी। भारत के लिए यह संतोष की बात है कि अमेरिका के दबाव से भारत सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि वे अमेरिकी दबाव के आगे भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि सहकारी मॉडल की रक्षा करना जरूरी है, ताकि किसान और दुग्ध उत्पादक सशक्त रहें। यदि भारत सरकार दबाव में आकर अमेरिका से डेयरी उत्पादों के आयात को मंजूरी दे देती है तो श्वेत क्रांति का सपना अधूरा रह जाएगा और सहकारिता आंदोलन पर घातक आघात होगा।

दुनिया के 140 देशों की आबादी से ज्यादा भारत में शिक्षक (यूडाइस प्लस की रिपोर्ट)

यूडाइस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फोर एजुकेशन) एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र से संबंधित आंकड़े और जानकारी एकत्र करता है। यूडाइस रिपोर्ट का उद्देश्य स्कूलों, स्कूलों में छात्र संख्या, शिक्षकों, विभिन्न सुविधाओं, और शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी प्रदान करना है। पाठकों को बताता चलूं कि यह रिपोर्ट शिक्षा नीति और योजना बनाने में सहायक होती है। हाल ही में आई यूडाइस-2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 140 ऐसे देश जिनकी आबादी से ज्यादा भारत में शिक्षक हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यह एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में शिक्षकों की संख्या कुछ देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मानव संसाधन निवेश कर रहा है। यह पहली बार है जब देश में स्कूली शिक्षकों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन फार सिस्टम एजुकेशन (यूडीआइएसई) प्लस की रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार शिक्षकों की संख्या में यह वृद्धि छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और शिक्षकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है क भारत के शिक्षा क्षेत्र में 2.9 लाख सरकारी स्कूलों में 2.6 लाख प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले शिक्षक कार्यरत हैं। यदि हम यहां पर शिक्षा तक पहुंच की बात करें तो रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 99% से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाता है। इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा का आंकड़ा भी बढ़ा है, जहां 80% से अधिक बच्चे 10वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रहे हैं। भारत में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 के आसपास है, जो कि एक सामान्य स्तर पर माना जाता है, हालांकि, यह राज्यवार भिन्न हो सकता है। यदि हम यहां पर शिक्षा पर खर्च की बात करें तो भारत सरकार ने शिक्षा पर 2024-25 में लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान रखा है, जिसमें एनसीईआरटी, स्मार्ट क्लास, और डिजिटल शिक्षा जैसे पहल शामिल हैं। भारत में 13 लाख से अधिक सरकारी स्कूल और 2.6 लाख से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें कुल मिलाकर 27 करोड़ से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों का नामांकन अब लगभग 50% हो चुका है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता की दिशा में सकारात्मक कदम है।इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 85% स्कूलों में पानी, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में इन सुविधाओं की कमी बनी हुई है।बहरहाल, यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह आंकड़े सुधार की दिशा में भारत की उपलब्धियों और चुनौतियों को दर्शाते हैं। बहरहाल, यह अच्छी बात है कि दुनिया के 140 ऐसे देश जिनकी आबादी से ज्यादा भारत में शिक्षक हैं, लेकिन किसी भी देश में अधिक संख्या में शिक्षक होना शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू जरूर हो सकता है, लेकिन कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता कई कारकों पर निर्भर करती है, और शिक्षक संख्या इसके एक हिस्से के रूप में काम करती है। यदि किसी देश में अधिक शिक्षक हैं, तो यह छात्रों के लिए अधिक व्यक्तिगत ध्यान, बेहतर कक्षाएं, और शिक्षण प्रक्रिया में लचीलापन सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन इसके लिए अन्य बुनियादी पहलुओं की भी नितांत आवश्यकता होती है। मसलन, शिक्षकों का प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी पहलू है। शिक्षकों का सही प्रशिक्षण और उनकी पेशेवर दक्षता भी जरूरी है। यदि शिक्षक अपने विषय में प्रवीण नहीं हैं, तो अधिक संख्या का कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा, संसाधनों की उपलब्धता एक अन्य जरूरी पहलू है। शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन जैसे पुस्तकें, डिजिटल उपकरण, कक्षा का वातावरण और अन्य सुविधाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहना ग़लत नहीं होगा कि शिक्षक और संसाधन दोनों मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।यह भी एक तथ्य है कि सरकारी नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ, और सुधार कार्यक्रम भी गुणवत्ता को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं। अगर शिक्षा नीति मजबूत नहीं है, तो शिक्षक और संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पाता।समाज और परिवार का योगदान भी एक अन्य जरूरी और महत्वपूर्ण पहलू है। छात्रों के घर का वातावरण और समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी अहम होती है। एक अच्छा वातावरण छात्रों के विकास में मदद करता है। इसलिए, अधिक संख्या में शिक्षक होना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन उसे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की दिशा में कारगर बनाने के लिए समग्र सुधार की आवश्यकता है। अंत में यही कहूंगा कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। मसलन, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, स्मार्ट क्लास रूम्स का निर्माण (तकनीकी उपकरण, ऑनलाइन संसाधन) बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आज जरूरत इस बात की है कि पाठ्यक्रम को अपडेट करके उसे समकालीन समाज और भविष्य की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए।केवल थ्योरी पर नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल और कौशल आधारित शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। व्यावहारिक शिक्षा दिया जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा में समावेशिता पर बल दिया जाना चाहिए। मसलन, गरीब, पिछड़े और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जाएं, ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए।मूल्य आधारित शिक्षा आज की महत्ती आवश्यकता है। मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को समाज, देश और परिवार के प्रति जिम्मेदारी, सहानुभूति, इमानदारी, समानता, और न्याय जैसी मूलभूत विचारधाराओं को सिखाने का काम करती है। छात्र-छात्राओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन शिक्षा को बेहतर बनाने में एक कारगर कदम साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आज स्कूलों की सुविधाओं में और भी अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि किताबों, प्रयोगशालाओं, और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आदि।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

आत्मबल से भरा है भारत

आज विश्व के एकीकरण का समय माना जाता है अर्थात वैश्वीकरण। यह वैश्वीकरण कुछ और नहीं बल्कि व्यापार की दृष्टि से देशों का आपस में जुड़ना है। जब व्यापार होगा तो एक दूसरे देश की सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराएं भी विस्तार लेती चली जाती हैं। वैश्वीकरण ने व्यापार के रास्ते खोलने के साथ-साथ समाज में नयापन भरा है, लोगों की सोच में भी परिवर्तन किया है। देश-विदेश की दूरियों को भी कम किया है।

आज भारत में अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई इसे भारतीय व्यापार पर कुप्रभाव की बात कर रहा है तो कोई आगामी परिणाम की बात कर रहा है। यदि हम थोड़ा सा पीछे हटकर देखें और बात करें तो प्रथम युद्ध का एक कारण यूरोपीय देशों का उपनिवेशवाद भी रहा। यह देश अपने लिए मंडी अर्थात बाजार खोज रहे थे।बाजार खोजते-खोजते इन यूरोपीय देशों ने एशिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। कई बार मन में प्रश्न उठता है कि एक छोटे से देश ने कैसे देखते ही देखते भारत जैसे विशाल भूखंड पर और इसकी प्राचीन सनातन संस्कृति पर अपना कुठाराघात किया। यह सत्ताधारी देश जिस देश पर अधिकार करते, उस देश की धन-संपदा तो लूटते ही थे साथ में वहां से कच्चा माल ले जाकर अपने देश के नाम पर विश्व में बेचकर मोटा पैसा कमाते थे। इन्होंने जिस भी देश पर अधिकार किया उस देश को चूस फेंका। गुलाम देशों में स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन होते रहे, यह व्यापार में पैसा कमाते रहे।हमारा भारतवर्ष भी उन दिनों ब्रिटिश शासन के अधीन गुलाम देश में से एक रहा।

ध्यान देकर देखें तो दूसरे विश्व युद्ध का बड़ा कारण वैश्विक आर्थिक मंदी रहा। यह आर्थिक मंदी भी पूरे यूरोपीय देशों और अमेरिका में ही रही। इन ताकतवर देशों ने अपने आसपास उभरते देशों को दबाना शुरू किया और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। एक दृष्टि से दोनों विश्व युद्ध की जड़ में बड़ा कारण आर्थिक लड़ाई ही रहा। कहने का भाव है कि यूरोपीय देश रहे हों या अमेरिका, ये हमेशा से ही वैश्विक बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसके लिए कितना ही बड़ा युद्ध क्यों ना हो जाए।

विचार करें तो अब वैश्विक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। विश्व के बहुत सारे देश स्वतंत्र रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जिन देशों पर अमेरिका या यूरोप अपना दबाव बढ़ाना चाहता है, वह देश उनसे किनारा करके अन्य देशों के साथ व्यापार करने पर तैयार हो जाते हैं। आज सभी के लिए सभी के कपाट खुले हुए हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रथम कार्यकाल से ही कहते रहे हैं मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ। दूसरी ओर देखेंगे तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वदेशी अपनाओ की बात महात्मा गांधी जी ने भी कही। इससे विदेशी लोगों की कमर अपने आप ही टूट गई।

आज हमारा देश हर क्षेत्र में कार्य कुशल है। अंतरिक्ष, विज्ञान, संचार, तकनीक आदि हर क्षेत्र में हमारे देश ने अपना लोहा विश्व को मनवाया है। कार्य और व्यापार के क्षेत्र में भी हम स्वावलंबी बनाकर अपनी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। हम स्वयं एक मजबूत स्थिति में है। भारतवर्ष आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को यह बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। जिस गति से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, हम तीसरे स्थान पर भी जल्द ही पहुंच जाएंगे।

अमेरिका रोज-रोज अपनी टैरिफ नीति में बदलाव कर रहा है। टैरिफ में बदलाव कर वह भारत पर दबाव बना रहा है। कैसे भी हो वह हमारे और वैश्विक बाजार को डुबो देना चाहता है। भारतवर्ष और अन्य उभरते देश आर्थिक रूप से टूट जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। 21वीं सदी का यह भारत कुछ नई दृष्टि और दृष्टिकोण से सोचता है। हमें शुद्ध व्यापार करना है, किसी भी देश से कर सकते हैं। छल, कपट, धोखा हम नहीं करते। हमारा देश आज मजबूत स्थिति में खड़ा है। धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। माना कुछ पक्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हम अपनी शर्तों पर काम करते हैं। भारतीय जनमानस का अपनी सरकार, अपने कार्य बल पर पूरा भरोसा है। देश दिनों-दिन विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। बाधाएं और कठिनाइयां तो रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव होते हैं, उन्हें पार करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

डॉ नीरज भारद्वाज

जस्टिस रेड्डी : संवैधानिक नैतिकता और हाशिये की आवाज़ों के रक्षक

(आलेख : एम श्रीधर आचार्युलु)

इंडिया गठबंधन द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय न केवल सराहनीय है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़ा होने का प्रतीक भी है।

वे भले ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच से सबसे चर्चित नामों में न रहे हों, लेकिन उनकी न्यायशास्त्रीय दृष्टि और फ़ैसले उनकी गहरी संवैधानिक चेतना के गवाह हैं। ख़ासकर हाशिये पर पड़े वर्गों की सुरक्षा और कार्यपालिका की मनमानी पर रोक लगाने में उनके निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए। सलवा जुडूम का फ़ैसला आज भी भारतीय संवैधानिक कानून का मील का पत्थर माना जाता है, जहाँ अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य की जवाबी कार्रवाई मौलिक अधिकारों की क़ीमत पर नहीं हो सकती।

न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखने की आस्था

1948 में जन्मे जस्टिस रेड्डी ने हैदराबाद के लॉ कॉलेज से विधि की पढ़ाई की। छात्र जीवन से ही उनमें संवैधानिक मूल्यों, न्याय और सामाजिक सरोकार के प्रति गहरी निष्ठा दिखने लगी थी। 1971 में वकालत शुरू करने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों व जनहित याचिकाओं में बेख़ौफ़ दलीलें रखीं।

1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। उनके फ़ैसले संविधान के प्रति गहरी निष्ठा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शी शासन की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। वे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे और आम नागरिकों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू कीं।

बेबसों के लिए ढाल

2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उसमें सलवा जुडूम फ़ैसले जैसी गूंजती हुई मिसाल शामिल है।

2011 में नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में उनके नेतृत्व वाली पीठ ने सलवा जुडूम आंदोलन को असंवैधानिक ठहराया। यह राज्य-समर्थित अर्धसैनिक अभियान था, जिसमें विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में अनपढ़-नासमझ आदिवासी युवकों को हथियार थमा दिए गए थे। फ़ैसले में कहा गया कि यह व्यवस्था न केवल अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है, बल्कि संविधानिक दायित्व से पलायन भी है।

जस्टिस रेड्डी ने साफ़ शब्दों में कहा कि नागरिकों को हथियारबंद कर हिंसक संघर्ष में झोंकना, राज्य का "संवैधानिक जिम्मेदारी से पलायन" है। यह फ़ैसला न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला था, बल्कि इसने यह मानक भी स्थापित किया कि कोई भी सुरक्षा नीति संविधान की चौखट से बाहर नहीं हो सकती। इसे भारतीय न्यायिक इतिहास में "न्यायिक मानवतावाद" का उज्ज्वल उदाहरण माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (2007–2011) जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडूम मामले के ऐतिहासिक फ़ैसले के ज़रिए भारतीय संविधान में अमूल्य योगदान दिया। इस निर्णय में उन्होंने आदिवासी समुदायों की रक्षा की और संवैधानिक मर्यादाओं को सुदृढ़ किया। न्याय और नैतिकता के प्रति उनका समर्पण केवल अदालत की बेंच तक सीमित नहीं रहा — लोकायुक्त और पर्यावरण निगरानी जैसे दायित्वों में भी उन्होंने संस्थागत ईमानदारी और भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र को मजबूत करने

का प्रयास किया।

विधायिका और न्यायपालिका की सीमाएं

फ़ैसले के बाद कई बार इसे दरकिनार करने की कोशिशें हुईं। लेकिन 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा स्पष्ट किया कि इस विषय पर नया कानून बनाना अवमानना नहीं होगा, पर मूल फ़ैसले की संवैधानिक आत्मा को बदला नहीं जा सकता। इस तरह जस्टिस रेड्डी द्वारा खींची गई संवैधानिक रेखा शासन और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की कसौटी बनी रही।

सेवानिवृत्ति के बाद भी संवैधानिक सेवाएं

सेवानिवृत्ति के बाद भी जस्टिस रेड्डी ने संवैधानिक मूल्यों को जिया। 2013 में वे गोवा के पहले लोकायुक्त बने। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के खनन प्रभाव क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय योजना की निगरानी का ज़िम्मा उन्हें सौंपा। यह उनके निष्पक्ष प्रशासनिक कौशल और पर्यावरणीय न्याय के प्रति भरोसे का प्रमाण था।

"हमारा संविधान हमारा है"

हाल ही में एक पुस्तक "संविधान की प्रस्तावना" के विमोचन अवसर पर उन्होंने उन बुद्धिजीवियों की आलोचना की, जो कहते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में भारत का नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान निर्माण के दिन ऑर्गेनाइज़र पत्र ने तिरंगे और संविधान दोनों को अस्वीकार किया था।

इस संदर्भ में उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के उत्तर को दोहराया कि यदि संविधान ने कई वैश्विक स्रोतों से अच्छे विचार अपनाए, तो इसमें शर्म कैसी — "अच्छे विचार चाहे जहाँ से मिलें, उन्हें अपनाना ही बुद्धिमानी है।" उन्होंने गांधीजी का कथन उद्धृत किया — "मेरे घर की सभी खिड़कियाँ खुली हैं, ताकि हर दिशा से अच्छे विचार भीतर आ सकें।"

उन्होंने यह भी कहा कि कृत्रिम रूप से गांधी और अम्बेडकर के बीच टकराव दिखाने की कोशिश करना बौद्धिक बेईमानी है।

नेहरू की दृष्टि और संघीयता

जस्टिस रेड्डी ने पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव की भी चर्चा की, जिसे उन्होंने 31 अप्रैल 1946 को पेश किया था। इसमें राज्यों को अधिक अधिकार और केंद्र को केवल आवश्यक शक्तियाँ देने की कल्पना की गई थी। उन्होंने आलोचकों से सवाल किया कि जो लोग नेहरू के योगदान को छोटा करते हैं, क्या वे उनकी बौद्धिक गहराई को समझते भी हैं?

न्यायपालिका का मानवीय चेहरा

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी आज न्यायिक नैतिकता, मानवाधिकार और संवैधानिक नैतिकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनकी उम्मीदवारी केवल एक संवैधानिक पद के लिए नामांकन नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों को बचाए रखने का संकल्प भी है। सलवा जुडूम फ़ैसला उनका स्थायी न्यायिक धरोहर है, जिसने दिखाया कि क़ानून महज़ शासन का उपकरण नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का साधन भी हो सकता है।

('न्यूज़क्लिक' से साभार। लेखक एम. श्रीधर आचार्युलु हैदराबाद में क़ानून के प्रोफ़ेसर हैं।)

महानदी जल विवाद समाधान केलिए आगे एक कदम उठाए ओडिशा, छत्तीसगढ़

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वरः महानदी विवाद के समाधान की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। ओडिशा सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्णकदम उठाया है।एक सार्थक बैठक में, दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सहयोगात्मक समाधान पर चर्चा की दोनों राज्य बातचीत के माध्यम से लोगों केहित मेंएक उचित समाधान खोजने केलिए

सहमत हुए हैं। इसलिए, सितंबर में, प्रत्येक राज्य के ईआईसी के नेतृत्व में गठित तकनीकी समितियां सप्ताह में एक बार महत्वपूर्ण मुद्दों पर बैठक करेंगी। समिति दोनों राज्यों के बीच महानदी जल बंटवारे में अधिक समन्वय के लिए एक संस्थागत ढांचे के विकास पर भी चर्चा करेगी। इसके बाद, मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव के स्तर पर एक और बैठक अक्टूबर में होगी। दिसंबर में, सुविधानुसार, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री काम की निगरानी करेंगे और दोनों राज्यों के लोगों के हित में महानदी जल विवाद के दीर्घकालिक और आम सहमति से समाधान के लिए आगे का रास्ता तय करेंगे। ओडिशा सरकार सभी के लिए समावेशी और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान केलिए खुले दिमाग से काम करने के लिए प्रतिबद्धहै।

राज्य स्वयत शासन दिवस पर बड़ी घोषणा: 7 नई नगर पालिकाओं और 16 ANAC का गठन

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वरः राज्यस्तरीय स्वायत्त शासन दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बड़ी घोषणा की। राज्य में 7 नई नगरपालिकाएं और 16 एएनएसी का गठन किया गया है। बौध, करंजिया, भंजनगर, आसिका, छत्रपुर, कविसूर्यनगर और पोलसारा को नगरपालिका का दर्जा दिया गया है।जिन नए एनएसी की घोषणा की गई है उनमें बलांगीर जिले में लोईसिंघा, बारगढ़ जिले में सोहेला, कटक जिले में बदम्बा, नरसिंहपुर और सालेपुर, ढेंकनाल जिले में गांडिया, गंजाम जिले में जगन्नाथप्रसाद और पात्रपुर, जाजपुर जिले में चंडीखोल, कालाहांडी जिले में नारला और जयपटना, खुर्दा जिले से टांगी, कोरापुट जिले में बोरीगुम्मा, मयूरभंज जिले में कप्तिपाड़ा, यशीपुर और रसगोबिंदपुर शामिल हैं।जिन नए एनएसी की घोषणा की गई है उनमें बलांगीर जिले में लोईसिंघा, बारगढ़ जिले में सोहेला, कटक जिले में बडम्बा, नरसिंहपुर और सालेपुर, ढेंकनाल जिले में गंदीआ, गंजाम जिले में जगन्नाथप्रसाद

और पात्रपुर, जाजपुर जिले में चंडीखोल, कालाहांडी जिले में नारला और जयपटना, खुर्दा जिले से टांगी, कोरापुट जिले में बोरीगुम्मा, मयूरभंज जिले में कप्तिपाड़ा, यशीपुर और रसगोबिंदपुर शामिल हैं।

मयूरभंज में करंजिया, जहां वर्तमान में एनएसी है, को एक नई नगर पालिका घोषित किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बौध जिले में बौध, गंजम जिले में भंजनगर, असखा, छत्रपुर, कविसूर्यनगर और पोलसरा को नई नगर पालिका घोषित किया है।

स्वार्थ का ज़हर...!

यारों फैल गया है स्वार्थ का ज़हर,
टूट रहा हैं अपनों पे बनकर कहर।
किसी की पीड़ा एवं किसी का दर्द,
यूं किसी को ना पड़ता कोई फ़र्क।
उनकी बातों में तो होती है मिठास,
अंदर ही अंदर वह पाले हैं खटास।

मदद का हाथ कोई यूं नहीं बढ़ाता,
यह भी हर किसी को नहीं सुहाता।
जिसकी किस्मत में हैं उसे मिलता,
ईमानदार भी हाथ मलते रह जाता।
अब रिश्ता भी सौदा हैं लगने लगा,
न जाने किस-किसको किसने ठगा।

संजय एम तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

"शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता"

हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। शहरी परिवार औसतन 3988 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना खर्च करते हैं। विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता कमजोर होने से अभिभावक मजबूर हैं। कोचिंग से शिक्षा असमानता और रटंत संस्कृति बढ़ रही है।

डॉ. प्रियंका सौरभ

आज शिक्षा का स्वरूप केवल कक्षा-कक्ष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह एक विशाल बाज़ार का रूप ले चुका है। हाल ही में आए सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों और कस्बों तक फैल चुकी है। शिक्षा, जो कभी घर-परिवार और समाज की साझा ज़िम्मेदारी मानी जाती थी, अब पूरी तरह बाज़ारीकरण और व्यवसायीकरण की चपेट में आ चुकी है।

कोचिंग संस्थानों का इतना व्यापक चलन इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कितनी कमज़ोर हो चुकी है। शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित है, स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अभाव है। यही कारण है कि अभिभावक अतिरिक्त खर्च उठाकर भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेज़ भेजने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा पर खर्च किसी परिवार के लिए केवल आर्थिक दबाव ही नहीं, बल्कि मानसिक बोझ भी है।

कोचिंग पर खर्च बढ़ने के पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बढ़ती होड़, नौकरी की असुरक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश की कठिनाइयाँ बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अतिरिक्त पढ़ाई की ओर धकेल देती हैं। शहरों में यह प्रवृत्ति और अधिक है क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता तीव्र है, वहीं गाँवों में भी धीरे-धीरे यह चलन गहराता जा रहा है।

यह प्रश्न केवल निजी खर्च का नहीं, बल्कि शिक्षा की दिशा और दशा का है। जब बच्चे स्कूल जाकर भी पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते और उन्हें वही विषय दोबारा कोचिंग में पढ़ना पड़ता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालयों की शिक्षण पद्धति में गंभीर खामियाँ हैं। शिक्षक यदि प्रेरक हों, पाठ्यपुस्तकें उपयोगी हों और वातावरण सकारात्मक हो तो बच्चों को स्कूल से बाहर कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े।

सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, जबकि शहरी परिवारों का यह खर्च लगभग 3988 रुपये सालाना है। यह अंतर केवल आय स्तर का ही नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुँच की असमानता का भी द्योतक है। शहरों में कोचिंग उद्योग संगठित रूप में कार्य कर रहा है, जबकि गाँवों में यह अधिकतर व्यक्तिगत ट्यूशन तक ही सीमित है।

एक और गंभीर पहलू यह है कि शिक्षा पर यह अतिरिक्त बोझ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गहरे संकट में डाल देता है। उच्च वर्ग के बच्चे महंगी कोचिंग और ट्यूशन से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे इसी कारण पीछे छूट जाते हैं। यह शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप पर आघात है, क्योंकि शिक्षा समान अवसर प्रदान करने का माध्यम होनी चाहिए, न कि असमानता को और बढ़ाने का कारण।

सरकार ने कई बार दावा किया है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कक्षा-कक्षों में शिक्षण की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है कि छात्र आत्मनिर्भर हो सकें। विद्यालयों को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने वाली प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित करना चाहिए।

कोचिंग पर निर्भरता एक और संकट खड़ा कर रही है — यह विद्यार्थियों को रटंत संस्कृति की ओर धकेल रही है। कोचिंग संस्थान सामान्यतः परीक्षा परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, वहाँ सृजनात्मकता या जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। इस प्रकार विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने की मशीन बनते जा रहे हैं, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं।

समाधान के रूप में सबसे पहले विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षक पदों की रिक्तियाँ तत्काल भरी जानी चाहिएँ, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए और शिक्षण पद्धति को अधिक व्यावहारिक तथा छात्र-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। जब तक विद्यालयों में विश्वास नहीं बनेगा, तब तक कोचिंग का यह बाज़ार यूँ ही बढ़ता जाएगा।

यह भी आवश्यक है कि शिक्षा नीतियों में इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि कोचिंग का दबाव लगातार बढ़ता गया तो यह नीति भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के बजाय सामाजिक ज़िम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।

आज समय की मांग है कि शिक्षा का बोझ बच्चों से कम किया जाए। उन्हें कोचिंग संस्थानों की दीवारों के बीच कैद करने के बजाय खुले वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाए। प्रतिस्पर्धा की भावना अच्छी है, लेकिन जब यह केवल आर्थिक सामर्थ्य पर आधारित हो जाए तो यह समाज में गहरी खाई पैदा करती है। शिक्षा का बाज़ार लगातार फैल रहा है और यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, शिक्षकों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई, और अभिभावकों का विश्वास वापस लाया गया, तभी हम कोचिंग पर निर्भरता कम कर पाएँगे। अन्यथा, हर तीसरा नहीं बल्कि हर दूसरा बच्चा भी कोचिंग की ओर भागता नज़र आएगा।

एन सी पी प्रदेश अध्यक्ष ने सुंदरगढ़ जिले में जब्त जमीनों को लेकर उठाए सवाल

विभिन्न जाँच एजेंसियों व विभागों द्वारा एटेच्ड की गई जमीनों व उन पर खड़े निर्माण से मुक्त कराया जाए

राउरकेला - शहर व उनके आसपास जिलों में भी विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर सील की गई जमीनों पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने कड़े सवाल खड़े किए हैं1 बीती सरकार के समय प्रशासन की मुक दृष्टि व मौन समर्थन से अरबों की जमीन आज विभिन्न स्थानों पर कब्जे में है या गेरकानूनी तरीके से आर ओ आर में परिवर्तित किये गए हैं1 वर्तमान में एनडीए सरकार के मुखिया मोहन मांझी जी एवं विशेष रूप से राजस्व मंत्री से इस विषय पर जरूरी हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि बीते समय में बेथेल

फाइनेंस, गोल्डन फॉरेस्ट व अन्य कई दर्जनों कई चिटफंड कंपनियों ने पेड़ लगाने के लिए व कई अन्य कल्पीत प्रकल्पों के नाम पर विभिन्न तहसीलों के अन्तर्गत एकड़ों में जमीन ली एवं इसके अलावा विभिन्न रेड के दौरान कई सरकारी एंव विभागीय जांच एजेंसीयों के द्वारा जमीनों पर आज खुलेआम बोर्ड लगाकर प्लाटिंग करना एवं सरकारी विभाग के गलत नीतियों के कारण इन जमीनों को आर ओ आर में परिवर्तित करना अपने आप में ही एक जांच का विषय है व इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के द्वारा जांचोंपरान्त इसे कब्जा मुक्त करने की अपील की है1 आज यह जमीने करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों के मूल्यों में है किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के कब्जे की प्रक्रिया में शामिल सरकारी कर्मचारी व अधिकारी व इस पूरे प्रकरण में अन्य संलग्न लोगों की भूमिका की भी जांच हो एवं जनता के गाढ़े पैसों से अर्जित कमाई से संलग्न सभी बहुमूल्य जमीनों को सरकारी खाते में दर्ज कराई जाए1

अमन अरोड़ा ने केंद्र से 60 हज़ार करोड़ रुपये की रोकी गई राशि जारी करने और बाढ़ मुआवज़े में 3 गुना वृद्धि करने की की मांग

केवल फोटो खिंचवाने की बजाय राज्य के लिए विशेष पैकेज सुनिश्चित करे पंजाब भाजपा नेतृत्व

'आप' के प्रदेश प्रधान अरोड़ा ने अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुक़सान का लिया जायज़ा

अमृतसर, 31 अगस्तः (साहिल बेरी)

अमृतसर ज़िले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये की रोकी हुई राशि तुरंत जारी करने और राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवज़ा राशि में तीन गुना वृद्धि करने की मांग की है।

अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्री अरोड़ा ने रविवार को अमृतसर के सर्किट हाउस में लोक निर्माण मंत्री स हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और विधायक स कुलदीप सिंह धालीवाल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

उन्होंने बाढ़ से हुए नुक़सान का जायज़ा लिया और ज़िला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार लोगों, उनके पशुओं और सामान की रक्षा करने के साथ-साथ भोजन और दवाइयों जैसी ज़रूरी आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। बाढ़ से हुए नुक़सान का आकलन करने की प्रक्रिया जारी है।

बाढ़ से बने संकट पर प्रकाश डालते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, जिस पर अधिकतर धान की खेती थी, जलभराव से प्रभावित है। कटाई से महज़ कुछ हफ़्ते पहले आई इस प्राकृतिक आपदा से फ़सलों को भारी नुक़सान हुआ है। इसके अतिरिक्त, पशुधन की हानि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी बड़ी चोट पहुँचाई है।

भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए श्री अमन अरोड़ा ने केंद्र पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए तुरंत सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पंजाब में 828 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परियोजना को रद्द कर दिया, जिसका लंबे समय तक ग्रामीण संपर्क सड़कों पर बेहद बुरा असर होगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु हस्तक्षेप करने और फंड जारी करने की अपील की गई है।

श्री अमन अरोड़ा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मौजूदा मुआवज़ा काफ़ी नहीं है। उन्होंने बताया कि फ़सलों के नुक़सान के लिए वर्तमान में प्रति एकड़ 6,800 रुपये दिए जाते हैं, जो अन्नदाता के साथ मज़ाक है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.20 लाख रुपये और मृत्यु की स्थिति में 4 लाख रुपये की राशि बेहद कम है। उन्होंने मांग की कि फ़सल के नुक़सान का मुआवज़ा किसानों को प्रति एकड़ 50 हज़ार रुपये दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य नुक़सानों के लिए भी मुआवज़ा उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री अरोड़ा ने बताया कि जीएसटी शासन लागू होने के बाद पंजाब को पिछले वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुक़सान हुआ है और ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) तथा मार्केट विकास फंड (एम.डी.एफ.) में 8,000 करोड़ रुपये रोक दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन तथ्यों के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य को न तो कोई मुआवज़ा दिया और न ही विशेष पैकेज।

श्री अमन अरोड़ा ने पंजाब भाजपा नेतृत्व से अपील की कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केवल फोटो खिंचवाने की बजाय राज्य के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज दिलाने का दबाव बनाएँ। उन्होंने ज़ोर देकर कहा— "यह समय है जब केंद्र सरकार को इस आवश्यकता की घड़ी में पंजाब की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।"

नॉर्थ विधानसभा में "आप" का कारवां हुआ मज़बूतः

रिंटू की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल के कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल

अमृतसर, (साहिल बेरी)

आम आदमी पार्टी की साफ-सुथरी राजनीति और जनहित की नीतियों के कारण पार्टी का परिवार प्रतिदिन बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से इंचार्ज करमजीत सिंह रिंटू ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया।

पार्टी की बढ़िया कारगुजारी और करमजीत सिंह रिंटू द्वारा नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन करवाए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के शिरोमणि अकाली दल के सदस्य गवर्निंग एडवोकेट संदीप सिंह भुल्लर, सर्कल प्रधान अजयपाल सिंह गिल, वरिष्ठ उपप्रधान सर्कल रणदीप सिंह बल, जत्थेबंदक सचिव अश्विनी सोई, उपप्रधान सर्कल मजीठा दलजीत कुमार ज्योति, कमलेश खैरदीन, जगीर सिंह खैरदीन, चंदीप सिंह संधू, धर्मिंदर सिंह गग्गा और सुरिंदर सिंह शिंदा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है।

करमजीत सिंह रिंटू ने इन नेताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होना माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया जी की ईमानदार राजनीति में लोगों के विश्वास का साफ संकेत है।

इस अवसर पर एडवोकेट सुखदेव सिंह भुल्लर और अन्य नेताओं ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी की जनहितकारी नीतियों और रिंटू जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़े हैं।

नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र इंचार्ज करमजीत सिंह रिंटू ने सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सभी चुनावी वायदे पूरे कर रही है और कई ऐसे फैसले भी ले रही है जो जनता के भले के लिए आवश्यक थे, भले ही वे वायदे घोषित न किए गए हों।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। रिंटू ने कहा कि "आप" सरकार एक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023